सैन्य सन्देश

Sainya Sandesh

युगाब्द 5126 अषाढ़–2081 जुलाई, 24

ओआरओपी-3 पर चर्चा

अखिल भारतीय पूर्व-सैनिक सेवा परिषद् का मुखपत्र

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

महराजगंज (उत्तर प्रदेश)

गोला गोकर्णनाथ (उत्तर प्रदेश)

बडोदरा (गुजरात)

झांसी (उत्तर प्रदेश)

देवरिया (उत्तर प्रदेश)

जयपुर (राजस्थान)

RNI Reg No.UPBIL/2002/9228

27. December 2023 Postal Reg. SSP/LW/NewsPaper-01-2024-2026
Despatched from- Lko RMS Non TD.
Dates of Despatch- 5,22 & 28

झलकियां : राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर, मथुरा-वृन्दावन

अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद

के सदस्य बनें और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें

मो. : 8317082620, 8004402890
Website: www.sainyasandesh.co.in
E-mail : sainyasandesh@gmail.com, info@sainyasandesh.co.in

सेवा में

अ.भा. पूर्व सैनिक सेवा परिषद् के लिए अतिथि मुद्रक एवं प्रकाशक कर्नल लक्ष्मीकांत तिवारी ने हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा, हजरतगंज, लखनऊ से मुद्रित कराकर, 3 नीवन मार्केट, बी.एन.रोड, कैसरबाग, लखनऊ से प्रकाशित किया।

सैन्य-सन्देश (मासिक)

राष्ट्रहित, समाजहित, सैनिक-हित को समर्पित पत्रिका

अखिल भारतीय पूर्व-सैनिक सेवा परिषद का मुख-पत्र

वर्ष–25 | आषाढ़–2081 | जुलाई, 2024

संरक्षक मण्डल

ले.ज.वी.के.चतुर्वेदी PVSM, AVSM,SM

ए.वी.एम. एच.पी. सिंह, VrC, VSM

प्रबन्धक मण्डल

ब्रिगेडियर डी एस त्रिपाठी

ब्रिगेडियर गोविन्दजी मिश्र VSM,PPM

सम्पादकीय सलाहकार

ले.जन. दुष्यन्त सिंह PVSM,AVSM

मुख्य सम्पादक

कर्नल लक्ष्मीकान्त तिवारी

सह-सम्पादक

सू.मे. जे.बी.एस. चौहान

प्रबन्धन विपणन एवं प्रचार-प्रसार

सू.मे. बी.एल. वर्मा

सू.मे. ए.के. दुबे

सीपीओ घनश्याम प्रसाद केसरी

सीपीओ डीडी पाण्डेय

(सभी पद अवैतनिक)

मुद्रित :

हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा लि0

प्रस्तुति

हिन्दी अनुभाग

1. संपादक की कलम से ''यही समय है, सही समय है'' 2
2. पटकथा पहले ही तैयार थी 3-4
3. चीन तो चीन है 5-6
4. राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग : 2024 7
5. चुनौतियां तो अब शुरु होती है 8-9
6. पंजाब को नागालैंड बनाने की साजिश 10-11
7. राष्ट्रवाद एक धर्म है.... 12
8. बीजिंग की बौखलाहट 13-14
9. करीबी मित्र को करीब रखने की चुनौती 15-16
10. जी 7 में विस्तार का वक्त 17-18
11. आतंकियो को संघर्ष विराम से मिली मदद 19
12. नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान..... 20
13. गीता स्कंद 'अष्टादश अध्याय' क्रमशः 21

English Section

1. Defeating the Diabolic Kashmir..... 22-23
2. Space Force Dynamics : Shaping the.... 24-25
3. Fighting the Dragon : India's Border..... 26-28
4. Why Should Be India Considering... 29-31
5. Inauguration of Captain Manoj Kumar.... 32
6. Welfare 33-34
7. गतिविधियां 35-36

सम्पादकीय कार्यालय : 3, नवीन मार्केट, बी.एन. रोड, कैसरबाग, लखनऊ–226001

मो. : 8004402890, 8317082620, 9651217002

Website: www.sainyasandesh.co.in

E-mail : sainyasandesh@gmail.com

The Publishers and Authors reserve the rights in regard to the contents of 'Sainya Sandesh'. The images and certain content used herein are from public domain, belongs to their respective owners and the same is being used herein for awareness and educational purposes only. The Magazine is non commercial, non profitable and intended to create awareness amongst soldiers community.

यही समय है, सही समय है

प्रोफेसर रिसाल सिंह का लेख पढ़ रहा था। बड़ा प्रसंगिक और सोचने पर मजबूर करने वाला था। आजकल की युवा पीढ़ी का एक वर्ग विवाह को एक अनावश्यक बुराई और बोझ के रूप में देखने लगा है। यह वर्ग उत्तरदायित्वहीन जीवन जीते हुए आनन्द उठाना चाहता है और विवाह जैसी सामाजिक जिम्मेदारी से बचना चाहता है।

केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने तलाक के एक मामले की सुनवाई करते हुए वर्तमान समय में वैवाहिक संबंधों की स्वार्थपरता और टूटन को रेखांकित किया है। न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति सोफी थॉमस की पीठ ने वर्तमान सामाजिक परिदृश्य पर अत्यंत सटीक टिप्पणी करते हुए समाज को आईना दिखाने का सराहनीय कार्य किया है। इस पीठ ने कहा है कि आजकल की युवा पीढ़ी का एक वर्ग विवाह को एक अनावश्यक बुराई और बोझ के रूप में देखने लगा है। यह वर्ग उत्तरदायित्वहीन जीवन जीते हुए आनन्द उठाना चाहता है और विवाह जैसी सामाजिक जिम्मेदारी से बचना चाहता है।

इसका विकल्प उसने 'लिव–इन' सम्बन्ध के रूप में ढूंढ निकाला है। युवा पीढ़ी का यह वर्ग पत्नी (वाइफ) को 'सदा के लिए समझदारी वाले निवेश' (वाइज इन्वेस्टमेंट फॉर एवर) की जगह 'हमेशा के लिए आमंत्रित चिंता' (वरी इन्वाइटेड फॉर एवर) के रूप में देखता है। लड़कियों के मन में पति को लेकर भी कमोबेश यही सोच हावी है। भले ही न्यायालय ने अपनी टिप्पणी का दायरा केरल के समाज तक सीमित रखा है लेकिन सच्चाई यह है कि इस प्रकार का चलन पूरे भारत में बढ़ रहा है।

शिक्षित, शहरी और समृद्ध वर्ग में भले ही यह प्रवृत्ति अधिक दिख रही हो लेकिन अशिक्षित/अल्पशिक्षित, ग्रामीण और गरीब तबका भी इससे अछूता नहीं है। विवाह संस्था के प्रति अनास्थावान युवा पीढ़ी पश्चिम प्रेरित और उपभोक्तावादी संस्कृति की शिकार है। यह विवाह संस्था को खोखला और निष्प्राण करने पर उतारू है। युवा पीढ़ी का यह वैचारिक प्रतिस्थापन चिंताजनक है। यह प्रवृत्ति बदलते जीवन–मूल्यों और प्राथमिकताओं का परिणाम है। निःसंदेह, न्यायालय की यह टिप्पणी सामाजिक विचलन की सार्वजनिक स्वीकृति और अभिव्यक्ति है।

कर्नल लक्ष्मी कान्त तिवारी
मुख्य संपादक

हमारा तिरंगा इसलिए नहीं फहरता है कि हवा चल रही होती है, बल्कि हमारा तिरंगा उस जवान की आखिरी सांस से फहरता है, जो हमारे तिरंगे की रक्षा के लिए अपने प्राणों को यूंही न्योछावर कर देता है!

Our tricolor does not fly because the wind is moving, but our tricolor flutters with the last breath of the young man who sacrificed his life to protect our tricolor!

पटकथा पहले ही तैयार थी

ब्रिटेन के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की हार की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था संकट से जूझ रही है, तो बढ़ती महंगाई ने भी जीना दूभर किया है। दरअसल, वहां चीजें बदल रही हैं, लेकिन ब्रिटेन इस हकीकत को देखने के लिए तैयार नहीं दिखता।

दीपक वोहरा

ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में 14 साल बाद लेबर पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है और कंजर्वेटिव पार्टी की बुरी तरह हार हुई है। ऋषि सुनक ने अपनी हार मान ली है और उन्होंने लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर को जीत की बधाई भी दी है। अब कीर स्टार्मर का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो गया है।

दरअसल, सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की हार की पटकथा लगभग उसी समय लिखी जा चुकी थी, जब बीते मई में निवर्तमान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अचानक चुनाव की घोषणा करके पूरे देश को चौंका दिया था। वास्तव में कंजर्वेटिव पार्टी को यकीन नहीं था कि वे शरणार्थियों (खासकर मुसलमानों) की रिकॉर्ड संख्या को आने से रोक पाएंगे। इस चुनाव में कंजर्वेटिव ने कई वादे किए, जिनमें कुछ शरणार्थियों को रवांडा भेजने की बेहद विवादास्पद योजना भी शामिल थी।

दूसरी तरफ, ब्रिटिश जनता कई समस्याओं से जूझ रही थी। जैसे बढ़ती महंगाई ने उनके घर का बजट बिगाड़ दिया। इसके अलावा, उन्हें लगता है कि अनियंत्रित इस्लामी शरणार्थियों की समस्या 'ब्रिटिश जीवन–शैली' को बर्बाद कर रही है, कभी दुनिया भर में प्रशंसित शिक्षा प्रणाली बर्बाद हो रही है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त हो गई है, लोगों को रहने के लिए सस्ता घर नहीं मिल रहा है और युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है। यहां तक कि प्रवासी भारतीय भी कंजर्वेटिव पार्टी से दूर जा रहे थे, क्योंकि ये समस्याएं उन्हें भी परेशान कर रही हैं।

चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाले इन मुद्दों से निपटने के बजाय निवर्तमान प्रधानमंत्री यूक्रेन युद्ध में रूस को हराने के लिए अमेरिकी रथ में सवार हो गए। करदाताओं का पैसा बेकार के प्रयासों में बर्बाद किया जा रहा है, जबकि यूक्रेन नष्ट हो चुका है।

असल में ब्रिटेन आज यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के अपने आत्मघाती कदम से जूझ रहा है, जिसने वहां की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। वह हताश होकर अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि बेहतर करना चाहता है, जबकि उसने वैश्विक मामलों में नाटकीय ढंग से अपनी कम हुई भूमिका

को स्वीकार नहीं किया है। इन्हीं वजहों से संसदीय चुनावों में लेबर पार्टी ने ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को आराम से हरा दिया।

लेबर पार्टी के उदय के लिए किसी लोकप्रिय नीति की तुलना में रूढ़िवादी विस्फोट को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कई प्रयासों के बाद एक दशक पहले भी ग्रेट ब्रिटेन बड़ी मुश्किल से स्कॉटिश स्वतंत्रता के जनमत संग्रह से बच पाया था। इस तरह का प्रयास फिर से होगा, क्योंकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। स्कॉटिश लोग फिर से यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। वैश्विक स्तर पर ब्रिटेन की प्रतिष्ठा बहुत नीचे गिर चुकी है। लंदन में अब वह बात नहीं रही। मई, 2024 में एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी ने माना कि दुनिया का 40 प्रतिशत अवैध धन लंदन में आता है। भ्रष्ट राजनेताओं, नौकरशाहों, व्यापारियों आदि द्वारा पैदा किए गए काले धन के लिए इंग्लैंड दुनिया की सबसे बड़ी पनाह बन गया है। भारत के कई घोषित आर्थिक अपराधी लंदन में छिपे हुए हैं, जिनमें से कुछ लोग भारतीय बैंकों के साथ की गई धोखाधड़ी के खिलाफ मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने की अपेक्षा ब्रिटिश जेल में रहना पसंद करते हैं। जबकि ब्रिटेन ने जुलाई, 1989 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के गठन में बहुत सक्रियता दिखाई, जिसका उद्देश्य मनी लॉन्डरिंग, आतंकवादियों को फंडिंग और सामूहिक विनाश के हथियारों की फंडिंग से निपटने के उपायों को विकसित करना था।

इंग्लैंड अतीतवाद से ग्रस्त है। वह कभी महान रह चुके अपने अतीत के साथ जीना पसंद करता है। जनवरी 2020 में, ब्रिटेन ने दुनिया के अग्रणी वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए फास्ट–ट्रैक वीजा देने की घोषणा की, जिसमें ब्रिटेन आने वाले योग्य लोगों की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। एक समय दुनिया का लगभग एक चौथाई हिस्सा ब्रिटेन के अधीन था। ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। हम भारत के लोगों ने ही दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का विध्वंस किया, क्योंकि हमने गैर–उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य ध्वस्त हो गया। 18वीं सदी के अंत में फ्रांसीसी क्रांतिकारी बर्ट्रेंड बारेरे ने एंगलटेरे (अंग्रेजों की भूमि) को दुकानदारों का देश बताया था, जो ईमानदार होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में धोखेबाज होते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान विश्वासघाती अंग्रेज फ्रांस में एक आम कहावत बन गई थी। सुनक ने हाल में कुछ गलतियां कीं, जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। जब वह कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब भी उनकी छवि को पार्टीगेट (कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री निवास में बोरिस जॉनसन के साथ जश्न मनाने) से झटका लगा था। संभवतः इससे भी ज्यादा नुकसान उन्हें वित्तीय मामलों को लेकर पारिवारिक विवाद के कारण हुआ। इसने उनकी लोकप्रियता को भारी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि कोविड सहायता योजना को लेकर उन्होंने अपनी अच्छी छवि बनाई थी, जिससे उन्हें परिवारों और व्यवसायों को बचाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई का श्रेय मिला था। हाल में उनकी आलोचना इसलिए हुई कि वह जीवन–यापन के संकट से जूझ रहे लोगों की मदद करने में सुस्त दिखे और लोगों से दूर होते दिखे। महंगी निजी वस्तुओं का दिखावा करने के चलते भी उनकी आलोचना हुई।

नवीनतम जनगणना के अनुसार, ब्रिटेन में गैर–ईसाई आबादी बढ़ रही है। अवैध प्रवासन के कारण मुसलमानों की संख्या वहां बढ़ रही है। इससे ब्रिटिश नाराज हैं। समय बदल जाता है, लेकिन मानसिकताएं स्थिर रहती हैं। यदि ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं होता, तो उसका वैश्विक प्रभाव सोमालिया के बराबर ही होता। हकीकत सामने है, लेकिन साम्राज्यवादी रवैया उसे स्वीकार करने से रोकता है। ऐसे में भला नस्लवादी अंग्रेज भारतीय मूल के ऋषि सुनक को कैसे बर्दाश्त करते? पता नहीं, सुनक ने इससे कुछ सबक सीखा या नहीं!

चीन तो चीन है

1958 में पं. नेहरू ने सेना के लिए संसाधनों की मांग को उस पंचशील समझौते की आड़ में ठुकरा दिया, जिसे चीन ने कभी नहीं माना।

शिवदान सिंह

कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से कहा कि भारत और चीन के बीच में स्थायी शांति के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान सबसे पहले जरूरी है। वर्ष 2020 में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद से ही पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। टकराव बढ़ने पर युद्ध भी हो सकता है।

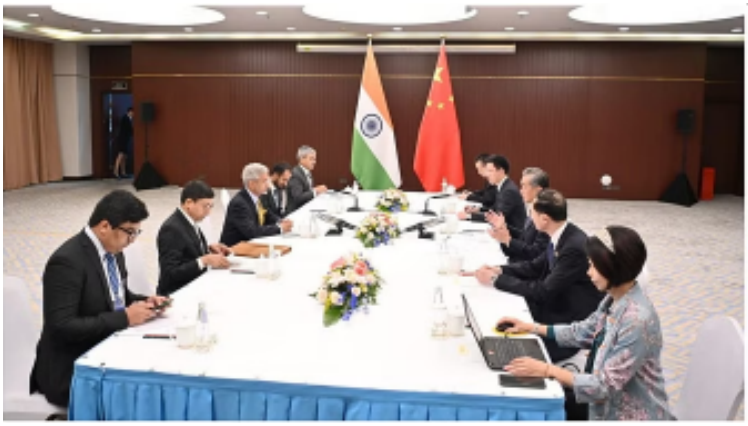

इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ा गया, जिसमें कहा गया कि सभी देशों को एक–दूसरे के क्षेत्र की संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। उनका इशारा चीन की तरफ था, जिसने 1955 से भारत का पूरा अक्साई चिन क्षेत्र अपने कब्जे में ले रखा है। भारत और चीन के बीच हुए 2010 के समझौते में साफ लिखा है कि दोनों देश एक–दूसरे की संप्रभुता का आदर करेंगे, लेकिन चीन की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। एस. जयशंकर ने भारत–चीन सीमा विवाद सुलझाने को अपनी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रखा है।

भारत और चीन के बीच तनाव का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नहीं होना है। 1916 में सीमा निर्धारण के लिए ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के बीच एक बैठक शिमला में हुई थी। भारत और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण हो गया था, जिसे मैकमोहन रेखा का नाम दिया गया था। हालांकि चीन सीमा निर्धारण पर सहमत नहीं हुआ था, उसने भारत– तिब्बत सीमा को भी अब तक मान्यता नहीं दी है। इसी कारण लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा को चीन विवादित मानता है। चीन के साथ विवाद सुलझाने के लिए जयशंकर को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल परनाइक, जो सेना की उत्तरी कमान के जीओओ सीएनसी रह चुके हैं, के विचारों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने हाल ही में कहा था कि चीन के साथ भारत के सीमा संबंधी

समझौतों में समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव की जरूरत है। अन्यथा चीन बार–बार सीमा उल्लंघन करता रहेगा और गलवान जैसी झड़पें होती रहेंगी।

चीन 1951 से ही भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। 1951 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन ने एक सड़क जी–21 का निर्माण किया। इसका काफी हिस्सा लद्दाख के अक्साई चिन से होकर गुजरता है। इसकी सूचना भारत सरकार को 1954 में मिल गई थी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके बाद भी 1954 में पं. जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ पंचशील समझौता किया, जिसका नारा था हिंदी चीनी भाई–भाई। भारत सरकार इस समझौते का पालन करती रही, लेकिन चीन ने इसे कभी नहीं माना। 1962 में चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया, जिसके कारण चीन की सेना अक्साई चिन से आगे भारतीय क्षेत्र में आ गई। चीनी घुसपैठ को देखते हुए 1958 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल थिमैया ने पं. नेहरू से सेना की तैयारी के लिए संसाधनों की मांग की, जिसे उन्होंने पंचशील समझौते की आड़ में ठुकरा दिया। देश की रक्षा के प्रति नेहरू के इस रवैये को देखते हुए जनरल थिमैया ने इस्तीफा दे दिया था। फिर चीन ने 1967 में सिक्किम पर कब्जा करने के लिए नाथुला पर हमला कर दिया, लेकिन उस समय मेजर जनरल संगत सिंह ने अदम्य साहस से चीनियों को पीछे धकेल दिया। हालांकि इसके लिए उन्हें दिल्ली से सहमति नहीं मिली थी।

वर्ष 1996 में सीमा पर शांति के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ कि सैनिक सीमाओं के बीच में नोमैंस लैंड पर बिना हथियारों के रहेंगे, लेकिन चीन ने इस समझौते की शर्तों को नकारते हुए गलवान में भारतीय सैनिकों पर कंटीले तार लगे हुए लाठी–डंडों से हमला किया। पड़ोसी के साथ शांति पूर्वक रहने के सिद्धांत को धता बताकर चीन ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों–मणिपुर, नगालैंड इत्यादि में आतंकवादी संगठनों को तैयार किया। हालांकि सेना ने उनका सफाया कर दिया। चीन की नजर अरुणाचल प्रदेश पर है। यदि चीन के साथ स्थायी शांति स्थापित करनी है, तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करना होगा। संयुक्त राष्ट्र को भी सीमा निर्धारण की बातचीत में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नहीं होने तक दक्षिण एशिया की इन दोनों शक्तियों के बीच में शांति स्थापित नहीं हो सकती।

सैन्य संदेश के सदस्य बनें

पत्रिका 'सैन्य संदेश' का सदस्य बनें। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के हर पदाधिकारी को पत्रिका का आजीवन सदस्य (Life Time Member) बनना अपेक्षित है। पत्रिका का वार्षिक शुल्क रू0 300/– और आजीवन सदस्यता शुल्क रू0 2500/– है। वार्षिक सदस्यों को एक वर्ष बाद पुनः सदस्यता नवीनीकरण अनिवार्य है जिसके लिये प्रति वर्ष रू0 300/– देय है। सदस्यता शुल्क आनलाइन पेयमेंट (Editor Sainya Sandesh A/c No. 0293000109102061 Punjab National Bank, IFS Code PUNB0029300) पर देय है। ऑनलाइन पेयमेंट का स्क्रीन शॉट सैन्य संदेश नेशनल whatsapp ग्रुप में या सम्पादक/सहसम्पादक/ कोषाध्यक्ष के फोन पर जो पत्रिका में सबसे पीछे के पृष्ठ पर अंकित है, भेजें। साथ में सब्सक्राइबर सदस्य का पोस्टल एड्रेस पिन कोड तथा मोबाइल नम्बर के साथ अवश्य भेजें।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग : 2024

(मथुरा–वृन्दावन)

– जे वी एस चौहान

अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग मथुरा–वृन्दावन (उ.प्र.) में 22–23 जून 2024 को आयोजित हुआ। इसमें प्रतिभाग के लिये राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ प्रदेश एवं प्रांतों के पदाधिकारी गण एवं सदस्यों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। दो दिन तक वृन्दावन के केशवधाम में चले प्रशिक्षण वर्ग में राष्ट्रीय अध्यक्ष ले.ज. वी के चतुर्वेदी पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम तथा पालक अधिकारी महोदय मा. प्रदीप जोशी भी उपस्थित हुए एवं प्रशिक्षण का निरीक्षण करते रहे। उन्होने भी अपने उदबोधनों द्वारा उपस्थित पूर्व सैनिकों का ज्ञान वर्धन किया। इसके अतिरिक्त निम्न गणमान्य पदाधिकारियो की उपस्थिति एवं उनका उद्‌बोधन उल्लेखनीय रहा –

1. मे.जन. (डा.) – राजीव पंत – सभाध्यक्ष
2. डा. जेपी शर्मा – राष्ट्रीय संगठन सचिव
3. कर्नल एल के तिवारी – रा.सचिव एवं वर्ग अधिकारी
4. मेजर आनंद टंडन – उत्तर प्रदेश संगठन सचिव
5. डा. देवेंद्र तोमर – उत्तर प्रदेश महासचिव
6. ब्रिगे. भुवनेश चौधरी – अध्यक्ष ब्रजपांत
7. कर्नल राजीव श्रीवास्तव – महासचिव पश्चिम बंगाल
8. कर्नल गोपाल सिंह – अध्यक्ष हरियाणा
9. श्री प्रहलाद सिंह एवं श्री विजय बोकिल – संस्थापक सदस्य
10. श्रीमती माया कौल – राष्ट्रीय संयोजिका मात्रृशक्ति

इस प्रशिक्षण वर्ग में कुल 134 पदाधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें मात्रशक्ति की उपस्थिति भी प्रशंसनीय रही।

दो दिन तक चले प्रशिक्षण वर्ग में सदस्यों ने अनुभवी एवं विद्वान पदाधिकारियों से संगठन हित में अपने ज्ञान को रिविव भी किया और बहुत सी नई जानकारियां हासिल की। नये सदस्यों के लिए यह वर्ग बहुत ही ज्ञान वर्धक रहा।

पालक अधिकारी महोदय मा. प्रदीप जोशी जी ने

सभी को आग्रह किया कि आप कोई भी कार्य संगठन हित में करते है तो आपको कार्य की स्पष्टता, कार्यपद्धति की स्पष्टता नियमित बैठकें और निश्चित समयांतराल में प्रवास करते रहने होंगे। सही समय पर सही एक्शन की आवश्यकता है। विमर्श की लड़ाई के लिए भी तैयार रहना है। अपने प्रवास में नये सदस्य बनायें एवं विरोधियो के गलत विमर्श की काट भी करते रहे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि हमारा ध्येय स्पष्ट है। संगठन नैतिक मूल्यों, संस्कारों, परम्पराओं और अनुशासन से चलता है। प्रधान मंत्री के पंच प्रणों पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया।

इस प्रशिक्षणवर्ग को आयोजित करने, इसकी सुगम एवं उत्तम व्यवस्था के लिये ब्रजप्रांत की टीम ने शानदार उदाहरण पेश किया। ब्रज प्रांत महासचिव श्री योगेंद्र सिंह की मेहनत एवं लगन की प्रायः सभी ने सराहना की। ब्रिगे. भुवनेश चौधरी एवं ब्रजप्रांत की टीम प्रशिक्षणाथियों एवं पदाधिकारियों के रहने एवं भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था के लिए बधाई की पात्र है। प्रदेशों/प्रांतो से आये पूर्व सैनिकों ने प्रशिक्षण के साथ साथ कान्हा की नगरी ब्रंदावन के भ्रमण एवं दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त किया। जय हिंद!

चुनौतियां तो अब शुरु होती हैं

—रोजर कोहेन

पेरिस ओलंपिक से ठीक पहले फ्रांस में चुनावी नतीजों ने एक गतिरोध तो पैदा कर ही दिया है। चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन प्रणाली के कारण गठबंधन की कोई संस्कृति नहीं है। ऐसे में, मैक्रों को अब भिन्न विचारों वाले दलों के बीच व्यापक सहमति वाले एजेंडे पर श्रमसाध्य बातचीत की बारीकियों को समझना होगा।

फ्रांस दक्षिणपंथियों के प्रभुत्व वाले देश के रूप में नहीं, बल्कि इटली की तरह एक ऐसे देश के रूप में जगा, जहां मुश्किल जोड़–तोड़ के जरिये ही सही, आखिरकार एक व्यावहारिक गठबंधन सरकार बन सकती है। फ्रांस ने संसदीय चुनाव में मरीन ली पेन की प्रवासन–विरोधी पार्टी नेशनल रैली को नकार दिया है, जो राष्ट्रवादी कारनामों के प्रति उनके गहरे प्रतिरोध का एक और प्रदर्शन था। फ्रांस की जनता ने अपनी पहली पसंद के रूप में फिर से उठ खड़े हुए वामपंथ को चुना जरूर है, लेकिन वह भी सरकार बनाने से काफी दूर है। इन स्थितियों ने मैक्रों को मजबूर कर दिया है कि वे सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति के बजाय संसद की भी सुनें। पेरिस ओलंपिक का बिगुल बजने में अब कुछ ही समय बचा है। अगस्त में समुद्र तटों या पहाड़ों पर जाना फ्रेंच जीवन–शैली की पहचान है। ऐसे में, यही लगता है कि सरकार के गठन की बातचीत शरद ऋतु तक खिंच सकती है, जब फ्रांस को बजट पारित करने के लिए सरकार की जरूरत होगी।

फिलहाल फ्रांस में चुनाव के नतीजों ने एक गतिरोध तो पैदा कर ही दिया है। एक उभरता हुआ और विवादास्पद वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट नेशनल असेंबली में 180 सीटें जीतकर पहले स्थान पर है। उसने तुरंत ही मांग की कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को उसे सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए। साथ ही उसने यह भी कहा है कि वह अगले हफ्ते अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री का नाम सामने रखेगा।

संविधान के अनुसार, मैक्रों ही प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। 577 सदस्यीय नेशनल असेंबली में न्यू पॉपुलर फ्रंट को बहुमत से करीब 100 सीटें कम हैं। उसकी जीत के पीछे सिर्फ वामपंथी गठबंधन नहीं था, बल्कि दूसरे चरण के मतदान में मध्यमार्गियों और वामपंथियों द्वारा नेशनल रैली के खिलाफ 'रिपब्लिकन मोर्चा' बनाने के निर्णय का असर भी दिखा था। इसके बावजूद, जुझारू वामपंथी नेता जीन–ल्यूक मेलेनचॉन ने कहा है कि वह संभावित गठबंधन सहयोगियों से बातचीत नहीं करेंगे, न ही वामपंथी कार्यक्रम में जरा भी बदलाव करेंगे। फ्रांस में राष्ट्रपति शासन प्रणाली के कारण गठबंधन बनाने

संबंधी समझौते की कोई संस्कृति नहीं है। मैक्रों को अब राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर भिन्न विचारों वाले दलों के बीच व्यापक रूप से सहमत एजेंडे पर श्रमसाध्य बातचीत की बारीकियों को समझना होगा। उदाहरण के लिए, न्यू पॉपुलर फ्रंट सेवानिवृत्ति की उम्र को 64 से घटाकर 60 करना चाहता है, जबकि एक साल पहले ही मैक्रों ने काफी संघर्ष के बाद इसे 62 से बढ़ाकर 64 कर दिया था।

मैक्रों बजट घाटे को कम करने को प्राथमिकता देना चाहते हैं, जबकि न्यू पॉपुलर फ्रंट न्यूनतम वेतन बढ़ाना चाहता है और ऊर्जा व गैस की कीमतों को स्थिर रखना चाहता है। मैक्रों की सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक आव्रजन विधेयक पारित किया था, जिसके तहत विदेशियों को फ्रांस में काम करने, रहने और पढ़ने की अनुमति देने वाले नियमों को सख्त बनाया गया था। जबकि, वामपंथियों ने शरण प्रक्रिया को और अधिक उदार बनाने का संकल्प लिया है।

नेशनल असेंबली का तीन बड़े गुटों–वामपंथी, मध्यमार्गी और दक्षिणपंथी–में विभाजन, किसी व्यावहारिक गठबंधन के लिए तत्काल कोई आधार प्रदान नहीं करता। मैक्रों के मध्यमार्गी गुट के पास लगभग 160 सांसद हैं, जो पहले 250 थे, तथा नेशनल रैली और उसके सहयोगियों के पास लगभग 140 सांसद हैं, जो पहले 89 थे। फ्रांस ने एक बार फिर अति दक्षिणपंथियों को सत्ता से दूर रखा, लेकिन आप्रवासन और जीवन–यापन की बढ़ती लागत के प्रति गुस्से के कारण दक्षिणपंथियों को सिरे से खारिज भी नहीं किया है। प्रधानमंत्री गैब्रियल अट्टल के साथ सोमवार को बातचीत के बाद मैक्रों ने उनसे देश की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए फिलहाल पद पर बने रहने के लिए कहा है।

मैक्रों का कार्यकाल सीमित है और उन्हें 2027 में पद छोड़ना होगा। वह पिछले कुछ दिनों से ज्यादातर चुप हैं, जो असामान्य बात है। हालांकि उनकी पार्टी एक–तिहाई सीटें गंवा चुकी है, लेकिन उनकी वैसी हार नहीं हुई, जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। अपमानित होने से वह बच गए। यह कोई छोटी बात नहीं है। अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह किसी गठबंधन की संभावनाओं को तलाशने के लिए विभिन्न दलों से आराम से परामर्श करेंगे। राष्ट्रपति के समक्ष दो चुनौतीपूर्ण विकल्प हैं। एक तो नेशनल रैली के साथ शासन करना, जिसके युवा पार्टी नेता जॉर्डन बार्डेला प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और दूसरे मेलेनचॉन की पार्टी के साथ सरकार बनाना, जिस पर मैक्रों ने यहूदी विरोधी होने का आरोप लगाया है। वह समाजवादियों और ग्रीन्स के साथ–साथ मुख्यधारा के रूढ़िवादियों सहित उदारवादी वामपंथियों को गठबंधन में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे।

पिछले महीने यूरोपीय संसद के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के सफल अभियान का नेतृत्व करने वाले ग्लक्समैन ने कहा, 'हम एक विभाजित असेंबली में हैं, और इसलिए हमें बचकाने व्यवहार से बचना होगा। इसका मतलब है कि हमें बात करनी होगी, संवाद में शामिल होना होगा और यह मानना होगा कि नेशनल असेंबली सत्ता का केंद्र है।' उन्होंने इसे 'राजनीतिक संस्कृति में एक मौलिक परिवर्तन' बताया। न्यू पॉपुलर फ्रंट की 180 सीटों में से अनुमानतः 75 सीटें फ्रांस अनबोड को मिलेंगी, जबकि लगभग 65 सीटें सोशलिस्टों को, लगभग 33 ग्रीन्स को तथा 10 से भी कम सीटें कम्युनिस्टों को मिलेंगी। जैसा कि ग्लक्समैन की टिप्पणियों से साफ है, गठबंधन को एक साथ बनाए रखना कठिन होगा।

सिद्धांत रूप में, यूरोपीय संसद में गठबंधन बनाने वाले उदारवादी ग्लक्समैन समाजवादियों, ग्रीन्स, कम्युनिस्टों, मैक्रों के मध्यमार्गी गुट और रिपब्लिकन के लगभग 60 मुख्यधारा के रूढ़िवादी सांसदों के गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन ग्लक्समैन का दृष्टिकोण मेलेनचॉन से टकराता है, जो संभावित साझेदारों के साथ बातचीत से इन्कार करते हैं, और वे मैक्रों के भी विरोधी हैं। इसलिए फिलहाल समझौते की कोई संभावना नहीं है। चुनाव के बाद फ्रांस में छाए धुंध से बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है।

पंजाब को नागालैंड बनाने की साजिश

पंजाब में 65000 पादरी, जिस चर्च के 14 साल पहले थे 3 मेंबर– अब हैं उसके 300000 सदस्य पंज प्यारों की जमीन पर 'पगड़ी वाले ईसाइयों' की छाया कैसे ....

भारत धर्मांतरण के घातक जाल में उलझा हुआ है। भोले–भाले जनजातीय समाज के लोगों को प्रलोभन दे ईसाई बनाने से मिशनरियों ने इस घातक जाल के धागे जोड़ने शुरू किए। अब यह एक ऐसे जाल के रूप में सामने आ चुका है, जिसमें दलित, पिछड़े, सर्वण सब उलझे नजर आ रहे हैं। इस घातक जाल की जद में पंजाब भी है। इंडिया टुडे मैगजीन ने पंजाब में ईसाई धर्मांतरण पर कवर स्टोरी की है। इससे जो तथ्य सामने आए हैं, वे बताते हैं कि यदि इस पर लगाम न लगी तो परिणाम घातक हो सकते हैं।

साल 2022 की शुरुआत में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए, तब यहाँ की आबादी का एक ऐसा वर्ग चर्चा में था जो खुद को दलित भी बताता है और ईसाई भी। वास्तव में ये वो लोग हैं जिन्हें मिशनरियों ने कन्वर्ट कर ईसाई बना दिया है। हालाँकि, आँकड़े यह कहते हैं कि राज्य की 1.26 फीसद आबादी ही ईसाई है। लेकिन, यहाँ बढ़ रहे धर्मांतरण के कारण जमीनी हकीकत पूरी तरह बदल चुकी है।

पंजाब में ईसाई मिशनरियों द्वारा सिखों के धर्मांतरण की स्थिति का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को सामने आकर धर्मांतरण विरोधी कानून की माँग करनी पड़ी है। यही नहीं, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि ईसाई मिशनरियाँ चमत्कारिक इलाज और कपट से सिखों का जबरन धर्म परिवर्तन करा रही हैं। पंजाब के सिखों और हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया था कि वोट बैंक की राजनीति के कारण सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और यहाँ के गरीब हिंदुओं और सिखों को धर्मांतरित करने के लिए 'विदेशी ताकतें' फंडिंग कर रही हैं।

यूँ तो पूरे पंजाब में ईसाई मिशनरी सक्रिय होकर सिखों को ईसाई बना रही है और ऐसा लगता है कि यह सब दबे पाँव हो रहा है। लेकिन, जालंधर जिले के खाँबड़ा गाँव में बने चर्च में प्रत्येक रविवार को प्रार्थना करने के लिए मोटर साइकिल से लेकर कारों और किराए की स्कूली बसों में पहुँचने वाले 10–15 हजार लोगों को देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि धर्मांतरण का 'बाजार' तेजी से फल–फूल रहा है।

इंडिया टुडे की कवर स्टोरी के अनुसार, इस गाँव में हजारों लोगों के जमा होने के पीछे जो व्यक्ति है उसका नाम है– पादरी अंकुर नरूला। अंकुर का जन्म हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। लेकिन, साल 2008 में ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आने के बाद उसने धर्मांतरण कर लिया। इसके बाद उसने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की स्थापना की और फिर 'चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स' भी शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि यहाँ निर्माणाधीन चर्च का निर्माण पूरा होने के बाद यह एशिया के सबसे बड़ा चर्च होगा।

शुरुआत में इस चर्च से जुड़े लोगों की संख्या महज 3 थी। लेकिन, बीते 14 सालों में यह संख्या 3 लाख के आँकड़े को पार कर चुकी है। अंकुर नरूला ने खाँबड़ा गाँव में 65 एकड़ से अधिक क्षेत्र में धर्मांतरण का साम्राज्य स्थापित किया हुआ है। इसके अलावा पंजाब के नौ जिलों व बिहार और बंगाल के साथ ही अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और ग्रेटर लंदन के हैरो में भी उसके ठिकाने हैं। अंकुर नरूला को उसकी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग या यह कहें कि धर्मांतरण का शिकार हुए लोग 'पापा' बुलाते हैं।

ऐसा कहा जाता है कि पंजाब में हो रहे धर्मांतरण के पीछे सबसे बड़ा हाथ नरूला का ही है। साल 2011 की

जनगणना के अनुसार, पंजाब में ईसाइयों की कुल जनसंख्या 348000 (3 लाख 48 हजार) थी। लेकिन, अब नरूला मिनिस्ट्री से जुड़े लोगों की संख्या ही 3 लाख से पार हो चुकी है। यानी राज्य में, ईसाई मिशनरियों के जाल में फँसकर 'पगड़ी वाले ईसाईयों' की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है।

जालंधर ही नहीं, अमृतसर में भी मिशनरियों ने सिखों को 'पगड़ी वाला ईसाई' बना दिया है। अमृतसर सिखों का पवित्र शहर है। यहीं पवित्र स्वर्ण मंदिर भी है। लेकिन यहाँ के सेहंसरा कलां गाँव की सकरी गलियों के बीच बना चर्च कथित तौर पर धर्मांतरण का केंद्र है। इस चर्च का पादरी गुरुनाम सिंह है जो कि एक पुलिसकर्मी भी है। इस चर्च में रविवार को प्रार्थना होती है। गुरुनाम सिंह का दावा है कि वह सिर्फ प्रार्थना कराता है। लेकिन, सवाल यह है कि यदि वह सिर्फ प्रार्थना कराता है तो लोग ईसाई कैसे बन रहे हैं?

ईसाइयों के लिए पंजाब धर्मांतरण की नई प्रयोगशाला नहीं है। लेकिन यहाँ सैकड़ों पादरी नए हैं। इन पादरियों में अमृत संधू, कंचन मित्तल, रमन हंस, गुरनाम सिंह खेड़ा, हरजीत सिंह, सुखपाल राणा, फारिस मसीह कुछ बड़े नाम हैं। इनका नाम इसलिए बड़ा है क्योंकि 'पगड़ी वाले ईसाइयों' की संख्या बढ़ाने में इनका बड़ा योगदान है। पंजाब में इनकी कई शाखाएँ हैं और यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स भी। ये सभी वे लोग हैं जो या तो पेशे से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस, कारोबारी और जमींदार हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो नौकरी या काम छोड़कर रविवार को प्रार्थना के नाम पर ईसाइयत का प्रचार करते हैं।

कपूरथला जिले के खोजेवाल गाँव में बना ओपन डोर चर्च पूर्वी यूरोपीय प्रोटेस्टेंट डिजाइन का है। इस चर्च के पादरी हरप्रीत देओल जट्ट सिख हैं, जिनके ऑफिस में बड़े–बड़े बाउंसर्स तैनात हैं। इसी प्रकार बटाला के हरपुरा गाँव के सर्जन–पादरी गुरनाम सिंह खेड़ा भी जट्ट सिख हैं। पटियाला के बनूर में चर्च ऑफ पीस के पादरी मित्तल बनिया हैं। चमकौर साहिब के रमन हंस मजहबी सिख हैं। इन पादरियों में से कई पादरियों के पास निजी सुरक्षा गार्ड भी हैं।

पंजाब में सिखों को ईसाई बनाने के तमाशे ने लाखों लोगों को चर्च तक पहुँचा दिया है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। हालत यह है कि ईसाई मिशनरी और नरूला जैसे लोगों की मिनिस्ट्री यहाँ के सभी 23 जिलों में फैली हुई हैं। ये मिशनरियाँ माझा और दोआबा बेल्ट के अलावा फिरोजपुर और फाजिल्का के सीमावर्ती इलाकों में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। पंजाब में ईसाइयत के प्रचार का बेड़ा उठाए लोगों की संख्या का कोई ठोस आँकड़ा नहीं हैं। लेकिन, इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमान के मुताबिक यहाँ पादरियों की संख्या 65,000 के करीब है।

कुछ समय पहले न्यूज नेशन ने यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट के आँकड़ों के हिसाब से बताया था कि पंजाब के 12,000 गाँवों में से 8,000 गाँवों में ईसाई धर्म की मजहबी समितियाँ हैं। वहीं अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में 4 ईसाई समुदायों के 600–700 चर्च हैं। इनमें से 60–70 प्रतिशत चर्च पिछले 7 सालों में अस्तित्व में आए हैं।

कुल मिलाकर आज पंजाब की कुछ–कुछ वैसी ही स्थिति तमिलनाडु जैसे दक्षिण के राज्यों में 1980 और 1990 के दशक में हुआ करती थी।

हालाँकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष एचएस धामी धर्मांतरण पर अधिक चिंतित नहीं हैं। उनका कहना है, "लोग जिंदगी की समस्याओं के हल के लिए पादरियों के पास जाते हैं। देर–सबेर उन्हें सच्चाई पता चलेगी और वे मूल धर्म में लौट आएँगे।" लेकिन 'घर घर अंदर धर्मसाल' जैसे अभियान बताते है कि स्थिति कितनी विस्फोटक हो चुकी है। इस अभियान के तहत सिख प्रचारक अपने धर्म का प्रचार करने घर–घर जा रहे हैं।

इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंज प्यारों की जमीन पर देखते–देखते ही कैसे 'पगड़ी वाले ईसाई' छा गए। इस सवाल का जवाब देने में जितनी देरी होगी, धर्मांतरण माफिया की जड़ें उतनी ही मजबूत होती जाएगी।

राष्ट्रवाद एक धर्म है जिसका स्रोत ईश्वर है

— महर्षि अरविंद

राष्ट्रवाद महज एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि राष्ट्रवाद एक धर्म है, जिसका स्रोत ईश्वर है। राष्ट्रवाद एक पंथ है. जिसे आपको जीना होगा। यदि आप राष्ट्रवादी बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर धार्मिक भावना का होना जब्ती है। साथ ही आपको याद रखना चाहिए कि आप ईश्वर के उपकरण हैं।

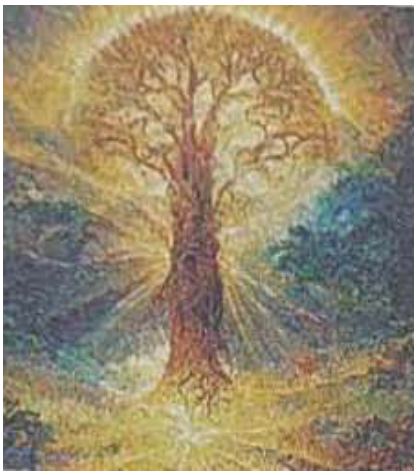

राष्ट्रवाद में किसी प्रकार के द्वेष, खिन्नता कड़वाहट या आक्रामकता की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आध्यात्मिकता पर आधारित मानव एकता के आदर्श को यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि अध्यात्मवाद ही राष्ट्रवाद का इकलौता सुरक्षा कवच है। राजनीति में लोगों का दिल से महान और उन्मुक्त होना आवश्यक है। अंतिम लक्ष्य मोक्ष के बजाय संपूर्ण मानव जाति का आध्यात्मीकरण जरूरी है। सरकार और समाज की मशीनरी के प्रयोग से अपने परिवेश को बेहतर बनाने एवं स्वप्न देख रहे मनुष्यों की यह पापमय स्पर्धा व्यर्थ है, क्योंकि बाल्य परिवेश को सुधारने के लिए अंतरात्मा की शुद्धता आवश्यक है। हमारा आचरण सहज व सरल और बौद्धिक रूप से चेत्तम हो। जो लोग कहते हैं कि भारत को एक राष्ट्र का दर्जा हासिल करने के लिए सबसे पहले जाति और धार्मिक मतभेदों को नष्ट करना होगा, उनकी धारणाएं हमारे राष्ट्र के चरित्र के बारे में काफी धुंधली और भ्रमित हैं। हमारा इतिहास अन्य देशों की तुलना में कई मायनों में भिन्न रहा है। भारतीय लोगों की संरचना पूरी दुनिया में अद्वितीय रही है। अतीत पर दृष्टि डालें, तो कई राष्ट्रों का विकास विभिन्न जनजातियों के एकत्रीकरण और समावेशन से हुआ है। यह बहुत पहले की प्रक्रिया है, किंतु भारत सिर्फ जनजातियों का मिलन स्थल नहीं रहा है, बल्कि अपनी विकसित सामाजिक और धार्मिक रेखाओं और मूल जातियों तथा विशिष्ट प्रकार की संस्कृतियों का मिलन स्थल रहा है। भारतीय राष्ट्र का चरित्र और संरचना, यूरोपीय राष्ट्रों से बहुत भिन्न है।

जीवन की वास्तविक पूर्णता जीवन के भौतिक पक्ष को नकार कर नहीं, बल्कि उसके आध्यात्मिक उन्नयन के माध्यम से ही संभव है। जीवन में भौतिक पक्ष का निषेध करने के कारण ही भारत को भौतिक परतंत्रता अंगीकार करनी पड़ी। हमें अपने वैयक्तिक जीवन की तरह राष्ट्रीय जीवन में भी आध्यात्मिक और भौतिक पक्षों का समायोजन करना होगा। जीवन जीवन होता है। भले वह एक बिल्ली का हो या फिर कुत्ते या मनुष्य का। बिल्ली और मनुष्य के बीच कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इन्सान के बीच मानवीय अवधारणा के लाभ का है। शत्रु कोई बाहर का नहीं होता, बल्कि यह हमारे अंदर बैठा हुआ है। ये शत्रु हैं—हमारा स्वार्थ, दुर्बलता और भावुकता। जब तक हम अपनी इन कमजोरियों को दूर नहीं करते, तब तक अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए अपने पुरुषार्थ को जागृत कर दृढ़ता के साथ खड़ा होना होगा।

बीजिंग की बौखलाहट

के एस तोमर

अमेरिका और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों की पृष्ठभूमि में तथा अमेरिकी संसद द्वारा पारित रिजॉल्व तिब्बत ऐक्ट को, जो तिब्बती लोगों को पूर्ण समर्थन देने का वादा करता है, अपनाने के बाद अमेरिकी संसद का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में भारत के धर्मशाला में दलाई लामा से मिला, जिससे चीन बुरी तरह भड़क गया। रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइकल मैककॉल के नेतृत्व में सात सदस्यीय उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने रिजॉल्व तिब्बत ऐक्ट के महत्व पर चर्चा की, जिसे राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जो तिब्बती लोगों के अधिकारों के प्रबल पैरोकार हैं।

इसी से संबंधित घटनाक्रम में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी और देश में हुए लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता, पारदर्शिता और व्यापकता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपना संदेश पोस्ट करते हुए लिखा कि 'प्रतिनिधिमंडल' में शामिल अमेरिकी संसद के मित्रों के साथ विचारों का बहुत अच्छा आदान–प्रदान हुआ। उन्होंने आगे कहा कि वह भारत–अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में मजबूत द्विदलीय समर्थन को 'गहराई से' महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट में दलाई लामा के साथ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की बैठक का उल्लेख नहीं है। रणनीतिक दृष्टि से इसे गुप्त रखा गया है। निर्वासित तिब्बती सरकार की मेजबानी करने वाले भारत का तिब्बत के साथ एक अनूठा संबंध है।

भारत सरकार अक्सर तिब्बती मुद्दे के प्रति अपने समर्थन और चीन के साथ व्यापक रणनीतिक व आर्थिक संबंधों के बीच संतुलन बनाते हुए कदम उठाती रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की धर्मशाला यात्रा के तुरंत बाद इस बैठक का समय चीन की आक्रामक नीतियों का मुकाबला करने में साझा मूल्यों और आपसी हितों को रेखांकित करने के लिए एक समन्वित कूटनीतिक प्रयास का संकेत देता है। जैसी की उम्मीद थी, चीनी दूतावास की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, जिसमें अमेरिका को गलत संदेश देने से बचने की चेतावनी दी गई। चीनी मिशन ने एक्स पर कहा, 'हम अमेरिकी पक्ष से आग्रह करते हैं कि वह दलाई समूह के चीन विरोधी अलगाववादी प्रकृति को पूरी तरह पहचाने, शिजांग मुद्दे पर अमेरिका ने चीन से जो वादा किया था, उसका सम्मान करे और दुनिया को गलत संदेश देना बंद करे।'

तिब्बती इतिहास एवं संस्कृति को कमजोर करने के लिए चीन तिब्बत को शिजांग कहता है, जिसे अक्तूबर,

1950 में उसने जबरन हड़प लिया था। दलाई लामा धर्मशाला में निर्वासित रहकर तिब्बती लोगों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। इन बैठकों पर चीनी प्रतिक्रिया संभवतः बहुआयामी होगी। कूटनीतिक मोर्चे पर बीजिंग वाशिंगटन और नई दिल्ली के समक्ष औपचारिक विरोध दर्ज कर सकता है। वह तिब्बत पर चीनी रुख को आंतरिक मामला बताते हुए उसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप की निंदा करेगा। हालांकि, व्यापक रणनीतिक निहितार्थ चीन के क्षेत्रीय कूटनीतिक दृष्टिकोण को फिर से निर्धारित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि तिब्बत के बारे में भारत और अमेरिका के विचार एक जैसे हैं और दोनों का रुख एक समान है, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि चीन ने 1962 में भारत के साथ धोखा किया, जिसे 2020 में दोहराया गया, जब लद्दाख में टकराव हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजिंग के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए गंभीर पहल की थी, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला है।

इन बैठकों से पता चलता है कि अमेरिकी और भारतीय हितों के मेल से एशिया में एक नई भू–राजनीतिक परिदृश्य का विकास हो रहा है। दोनों देश खासकर हिंद–प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और आक्रामक व्यवहार के प्रति समान रूप से आशंकित हैं। अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए अमेरिका और भारत चीनी महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए एक नियम–आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता जता रहे हैं। बदले में चीन अपने गठजोड़ को मजबूत करने और क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने पर जोर दे सकता है। इसके तहत वह पाकिस्तान के साथ संबंधों को गहरा कर सकता है, अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ भागीदारी बढ़ा सकता है और रणनीतिक पैठ जमाने के लिए अपनी बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाओं में तेजी ला सकता है। इसके अलावा, चीन भारत के साथ विवादित सीमाओं पर अपनी सैन्य स्थिति को बढ़ा सकता है, खासकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के विवादास्पद क्षेत्रों में, ताकि अपने क्षेत्रीय दावों को पुख्ता किया जा सके।

तात्कालिक रणनीतिक गणनाओं से परे, ये बैठकें लोकतांत्रिक मूल्यों और तानाशाही शासन के बीच व्यापक वैचारिक प्रतिस्पर्धा को भी उजागर करती हैं। अहिंसक प्रतिरोध और आध्यात्मिक नेतृत्व के प्रतीक दलाई लामा उन मूल्यों के प्रतीक हैं, जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों की वैश्विक पैरोकारी करते हैं। उनके साथ जुड़कर, अमेरिका और भारत इन सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ, चीन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को बचाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तिब्बत, शिनजियांग और हांगकांग में चीनी गतिविधियों पर बढ़ती वैश्विक निगरानी बीजिंग को रक्षात्मक स्थिति में ले आई है। वैश्विक प्रभाव की लड़ाई में, सॉफ्ट पावर और नैतिक अधिकार तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। धर्मशाला और दिल्ली की बैठकें अमेरिका और भारत के सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे उन्हें मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों का अगुआ माना जाता है।

जैसे–जैसे एशिया में भू–राजनीतिक बिसात जटिल होती जाएगी, कूटनीति और प्रतिरोध के बीच का अंतर–संबंध महत्वपूर्ण होता जाएगा। अमेरिका और भारत, अपने समन्वित कूटनीतिक कार्यों से, चीन का मुकाबला करने के लिए अधिक मुखर और सहयोगी दृष्टिकोण का मंच तैयार कर रहे हैं। इसमें न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना शामिल है, बल्कि हिंद–प्रशांत क्षेत्र में समान विचारधारा वाले देशों के साथ व्यापक गठजोड़ को बढ़ावा देना भी शामिल है।

करीबी मित्र को करीब रखने की चुनौती

भारत का दूसरा दौरा कर शेख हसीना ने संदेश दे दिया है। देखना यह है कि भारत राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बगैर बांग्लादेश को क्या दे सकता है।

महेन्द्र वेद

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पंद्रह दिनों के भीतर दूसरी बार भारत की यात्रा पर आयीं। प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत करना चाहते हैं। पर यह इस पर भी निर्भर करता है कि भारत बांग्लादेश को क्या दे सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और हसीना, दोनों दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जटिल राजनीतिक व भू–राजनीतिक गतिशीलता से वाकिफ हैं, जिसमें क्वाड चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। अनुमान लगाया जा सकता है कि चीन को अलग–थलग करने के लिए भारत ऐसे प्रस्ताव देगा, जिन्हें वह आसानी से मना नहीं कर पाएंगी। इससे हसीना को अगले महीने चीनियों से बातचीत में भी कुछ लाभ मिलेगा।

शेख हसीना ने चीन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास स्थगित कर दिया है। भारत रक्षा पर 50 करोड़ डॉलर की क्रेडिट लाइन का शीघ्र कार्यान्वयन चाहता है। हसीना ने तीस्ता नदी के विकास में वित्त पोषण और भागीदारी के चीन के प्रस्ताव को भी टाल दिया। समझौते के अनुसार, इसके पानी के समान बंटवारे की बांग्लादेश की पुरानी मांग है। लेकिन भारत इसे पूरा करने में असमर्थ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल इससे सहमत नहीं है। इस बार भी समझौते की संभावना नहीं दिखती है। वर्ष 2026 में गंगा जल संधि खत्म हो जाएगी, जिसे परस्पर संतुष्टि के लिए फिर से नवीनीकृत किया जाना चाहिए। यदि भारत इसमें चूक जाता है, तो चीन को बांग्लादेश को अपने पाले में लाने की कोशिश करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए भारत को अपने 'सबसे करीबी' और 'मित्रवत' पड़ोसी की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। भारत और बांग्लादेश, दोनों के पास दीर्घकालिक दृष्टिकोण हैं, जिसे पूरा करने के लिए सहयोग की जरूरत है। भारत 2047 तक 'विकसित' राष्ट्र बनना चाहता है और बांग्लादेश, 'स्मार्ट' राष्ट्र। आर्थिक विकास व सामाजिक सामंजस्य दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं। मनुष्यों (कथित अपराधियों समेत), मवेशियों, हथियारों और नशीले पदार्थों की

सीमा पार अवैध आवाजाही पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।

बांग्लादेश को भारत से ऋण की उम्मीद है। इसके लिए वह चीन से भी संपर्क करेगा। हालांकि हसीना की इस यात्रा के दौरान किसी नए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है, पर ऐसी घोषणा संयुक्त विज्ञप्ति में की जा सकती है। भारत परस्पर लाभ के लिए निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते का तेजी से क्रियान्वयन चाहता है।

वर्ष 2010 से भारत ने बांग्लादेश को 7.36 अरब डॉलर का ऋण देने का वादा किया है। बांग्लादेश इस साल अप्रैल तक केवल 1.73 अरब डॉलर या वादे का 23 प्रतिशत ही उपयोग कर पाया है। मौजूदा भारतीय क्रेडिट लाइन की शर्तें बहुत सख्त हैं। जैसे, हर परियोजना के लिए लगभग 65–75 प्रतिशत सामान या सेवाएं भारत से खरीदी जानी चाहिए, जिससे परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हो रही है। हसीना ने सोनादिया बंदरगाह को विकसित करने के चीनी प्रस्ताव पर कहा कि उसे उम्मीद है कि भारत इसकी भरपाई करेगा। भारत एक नई द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के लिए उत्सुक है, और मोंगला समुद्री बंदरगाह में व्यापक भूमिका निभाना रहा है। हिंद–प्रशांत तक विस्तारित एक नया समुद्री मार्ग भी एजेंडे में है।

इसके अतिरिक्त, भारत का लक्ष्य समुद्री सहयोग को बढ़ाते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में सागर परियोजना का विस्तार करना है। बांग्लादेश का लक्ष्य भूटान से अधिक जलविद्युत आयात करना है, जिसके लिए भारत की सहमति की आवश्यकता है। उम्मीद है कि भारत भूटान से बांग्लादेश तक बिजली पहुंचाने के लिए अपने क्षेत्र के इस्तेमाल पर सहमत हो सकता है।

दोनों देशों के बीच सार्वजनिक परिवहन के लिए फेनी मोइत्री (मैत्री) पुल का जल्द उद्घाटन करने और रामपाल मोइत्री बिजली संयंत्र की दूसरी इकाई खोलने के लिए चर्चा चल रही है। द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों परियोजनाओं को प्रतीकात्मक रूप से खोले जाने की उम्मीद है। दक्षिण त्रिपुरा जिले में भारत–बांग्लादेश को जोड़ने वाले मैत्री सेतु के माध्यम से यात्री आवागमन इस साल सितंबर तक शुरू होने वाला है। इसमें शामिल जटिलताओं को देखते हुए शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया है। उस यात्रा के दौरान इनमें से कुछ मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। जाहिर है, दोनों पड़ोसियों को मिलकर काम करना चाहिए, चाहे चीन का प्रभाव हो या न हो।

Advertisement Rate : Sainya Sandesh Patrika

No.	Size	One Time Tariff	Annual Tariff	Remarks
01	Seasonal Greetings	Rs. 800/=		
02	B/W half page	Rs. 8000/=	Rs 96,000/- (1x month complementary)	
03	B/W Full page	Rs. 10,000/=	Rs 1,20,000/- (1x month complementary)	
04	Colour Full page (inner page)	Rs. 14,000/=	Rs 1,68,000/- (1x month complementary)	
05	Colour Full page (Rear page)	Rs. 16,000/=	Rs 1,92,000/- (1x month complementary)	

जी 7 में विस्तार का वक्त

प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ व्यक्तिगत रिश्ते बनाने में अनूठी महारत हासिल की है। भारत की जनसंख्या जी–7 देशों की कुल आबादी से दोगुनी है, तो भारत का जीडीपी जी–7 के चार सदस्यों से ज्यादा है। अब समय आ गया है कि भारत को जी–7 का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया जाए।

सुरेन्द्र कुमार

सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सेल्फी की भरमार है। वह कॉलेज जाने वाली किशोरी की तरह लग रही हैं, जो अपने हीरो के साथ सेल्फी लेकर बहुत खुश और अभिभूत हैं और उत्साह में चिल्लाती हैं–मेलोडी (मेलोनी और मोदी) टीम की ओर से हेलो! प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर आलोचक भी यह स्वीकार करेंगे कि हमारे सत्तर वर्षीय प्रधानमंत्री ने अलग– अलग तरह के वैश्विक नेताओं के साथ गर्मजोशी, मिलनसारिता और व्यक्तिगत रिश्ते बनाने में अनूठी महारत हासिल कर ली है।

उन्हें केवल आउटरीच सेशन में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन सामूहिक तस्वीर लेते वक्त उन्हें प्रमुखता से केंद्र में रखा गया। संक्षेप में कहें, तो उनके प्रति काफी सम्मान और शिष्टाचार दर्शाया गया। और हो भी क्यों नहीं? अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपतियों तथा ब्रिटिश एवं कनाडा के प्रधानमंत्रियों (जनमत सर्वेक्षणों में जिनकी लोकप्रियता घट गई है और अनिश्चित राजनीतिक भविष्य का सामना कर रहे हैं) की तुलना में मोदी ने भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया है, हालांकि उनकी अपनी पार्टी लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई।

इस अवसर का लाभ उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसे मुद्दे उठाए, जो न सिर्फ भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। एआई और ऊर्जा, अफ्रीका एवं भूमध्यसागर पर जी–7 के आउटरीच सेशन में उन्होंने कई विषयों पर प्रकाश डाला, मुख्य रूप से मानव प्रगति में प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग पर। मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रौद्योगिकी के उदय ने साइबर सुरक्षा के महत्व की भी पुष्टि की है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत अपनी विकास यात्रा के लिए किस तरह से एआई का लाभ उठा रहा है। यह जरूरी है कि एआई पारदर्शी, सुरक्षित, सुलभ और जिम्मेदार बना रहे। जहां तक ऊर्जा का सवाल है, भारत का दृष्टिकोण उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य और स्वीकार्यता पर आधारित है। हम निर्धारित समय से पहले अपनी कॉप प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। भारत लाइफ (एलआईएफई) मिशन के सिद्धांतों के आधार पर हरित युग की शुरुआत करने के लिए काम कर रहा

है। प्रधानमंत्री मोदी ने धरती को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि समय से पहले कॉप प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला भारत पहला देश होगा और यह 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

सितंबर, 2023 में जी–20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी यूनियन को उसका पूर्ण सदस्य बनवाने के भारत के प्रयासों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की भलाई के लिए बोलने और विश्व मंच पर अपनी प्राथमिकताओं और चिंताओं को व्यक्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत–इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने भारत–प्रशांत और भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की आशा व्यक्त की।

पिछले दो दशक से ज्यादा समय से हम सुन रहे हैं कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जन्मी मौजूदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) आज दुनिया की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती और उसकी समस्याओं का समाधान करने में अक्षम है। यही बात जी–7 के साथ लागू होती है, जिसकी स्थापना 1975 में दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक लोकतंत्रों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान) के एक अनौपचारिक समूह के रूप में तेल संकट, वित्तीय संकट और मंदी से निपटने के लिए की गई थी। इस समूह में कनाडा 1975 में शामिल हुआ। इसका न तो मुख्यालय है, न सचिवालय और न ही चार्टर। इसकी अध्यक्षता बारी–बारी से हर साल सदस्य देशों द्वारा की जाती है। मौजूदा अध्यक्ष एजेंडा निर्धारित करता है और गैर–सदस्य देशों को उचित समझकर आमंत्रित करता है। पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक चिंताओं के अलावा जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रवासन जैसे कई मुद्दे जी–7 की चर्चाओं में प्रमुखता से शामिल रहे हैं।

जी–7 देशों की कुल जीडीपी, जो विश्व की जनसंख्या का मात्र 10 फीसदी है, 463 खरब डॉलर है। आईएमएफ के अनुसार, 2023 में यह वैश्विक जीडीपी का 26.4 फीसदी रह गया है, जबकि 2000 में यह 40 फीसदी था। हालांकि वर्तमान में ब्रिक्स की जीडीपी लगभग 260 खरब डॉलर होने का अनुमान है। गोल्डमैन सैक को लगता है कि 2050 तक ब्रिक्स जी–7 की जीडीपी से आगे निकल सकता है! यदि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और अर्जेंटीना जैसे देशों को इसमें शामिल कर लिया जाए, जिन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने में रुचि दिखाई है, तो यह काम पहले भी हो सकता है। अकेले भारत की जनसंख्या पूरे जी–7 देशों की कुल आबादी से दोगुनी है और भारत का वर्तमान जीडीपी (39.40 खरब डॉलर) जी–7 के चार सदस्यों–इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा के जीडीपी से ज्यादा है। ऐसे में, भारत को शामिल किए बिना जी–7 वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कैसे कर सकता है और व्यावहारिक समाधान कैसे निकाल सकता है?

अब समय आ गया है कि भारत को जी–7 का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया जाए, न कि आउटरीच सत्रों के लिए। अभी अमेरिका, जिसका जीडीपी जी–7 के कुल जीडीपी का 50 फीसदी से अधिक है, समूह के अन्य सदस्यों के समर्थन के कारण गैर–सदस्य देश के खिलाफ प्रतिबंधों सहित कोई भी निर्णय पारित करवा सकता है। भारत के शामिल होने से उस मनमानी को कुछ हद तक चुनौती मिलेगी। अगर इसमें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन को शामिल नहीं कर सकते, तो उन्हें ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे लोकतंत्रों को शामिल करना चाहिए और इसका नाम जी–10 रखना चाहिए। भारत और ब्राजील आईएमएफ में उच्च मतदान अधिकारों के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन और जापान की मदद से अमेरिका आसानी से ऐसी मांगों को टाल सकता है। अब समय आ गया है कि जी–7 के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी बदलाव हो।

आतंकियो को संघर्ष विराम से मिली मदद

पाकिस्तान के साथ 2021 में संघर्ष विराम हुआ। नियंत्रण रेखा शांत है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए घुसपैठ कराना आसान हो गया है। उसने आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों को फिर से सक्रिय कर दिया है। इसी का नतीजा है कि जम्मू–कश्मीर में तबाह हो चुका आतंकी नेटवर्क एक बार फिर सक्रिय हो गया है।

मे.जन. जीडी बख्शी

आतंकी संगठन अब जम्मू क्षेत्र को निशाना बना रहे हैं। लगातार इस तरह के हमलों से साफ है कि आतंकियों ने इस क्षेत्र में अपनी जड़े फिर से जमा ली हैं। भौगोलिक दृष्टि से समझें तो ज्यादातर हमले पीर पंजाल के दक्षिण क्षेत्र में हो रहे हैं। यह पूरा क्षेत्र घना पहाड़ी जंगल है और कुछ मीटर भी देखना संभव नहीं है। पाकिस्तान से आने वाले आतंकी इसका फायदा उठाकर सुरक्षाबलों पर हमला करते हैं और फिर जंगल में ही भाग जाते हैं और इस क्षेत्र में बने ठिकानों में छिपे रहते हैं।

वर्ष 2,000 के आसपास यह क्षेत्र आतंक का गढ़ बन चुका था। कश्मीर से अधिक हमले इसी क्षेत्र में होते थे। राजौरी–पुंछ से लेकर डोडा–किश्तवाड़ – और रियासी में एक के बाद कई नरसंहार हुए और उसके बाद शासन चेता और सेना को आतंक के सफाए के लिए खुली छूट दी गई। 2004 में पुंछ में हिलकाका पर आपरेशन सर्प विनाश को अंजाम दिया गया। अन्य जिलों में भी सेना की रोमियो फोर्स ने आतंकियों को खोज–खोजकर मारना शुरू कर दिया। उसके बाद इन आतंकियों को कोई ठौर नहीं मिली। लगभग दो दशक की शांति के बाद इस क्षेत्र में आतंकी न केवल जड़ें जमा चुके हैं बल्कि सेना के शौर्य को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं। आवश्यकता यह समझने की है कि ऐसे क्या हालात बने कि हम इस क्षेत्र में अमन की रक्षा नहीं कर पाए।

इस क्षेत्र में अतंकियो को सुरक्षित ठिकाने कैसे मिल रहे है, जब कि यहा की मूल आबादी सदैव आतंक के खिलाफ संघर्ष में सेना का साथ देती रही है। पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों के कारण ऐसे लोगों को नदी नालों और खड्डों के आसपास लगाया गया, जिनकी भूमिका सदैव संदिग्ध रही है। इन्हीं नालो के आस–पास आतंकियों को ठिकाने मिल रहे हैं और वह वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से निकल जा रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि हमने पाकिस्तान के साथ 2021 में संघर्ष विराम किया और इसका फायदा लगातार पाकिस्तान उठा रहा है। चूंकि अब नियंत्रण रेखा शांत है और पाकिस्तान के लिए इस क्षेत्र में आतंकियों की घुसपैठ कराना सुगम हो गया है। इस दौरान नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का पाकिस्तान ने फायदा उठाया और एलओसी के उस पार तबाह हो चुके अपने प्रशिक्षण केंद्रों को फिर से सक्रिय कर दिया और लगातार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करता रहा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। यही वजह है कि एक समय जम्मू कश्मीर में लगभग तबाह हो चुका आतंकी नेटवर्क फिर से सक्रिय हो चुका है।

जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद पीर पंजाल के उत्तर क्षेत्र अर्थात दक्षिण कश्मीर में हमने सुरक्षा घेरा इस तरह से कसे रखा कि आतंकी और उनके समर्थक कसमसा कर रह गए। वहीं, शांत दिख रहे पीर पंजाल के दक्षिण क्षेत्र पर हमारी चौकसी कम होती गई। इस क्षेत्र में सुरक्षाबल पहले से ही कम थे। ऐसे में पाकिस्तान ने आतंकियों के अपने नेटवर्क को पहले राजौरी–पुंछ तथा डोडा जैसे जिलों में फिर से सक्रिय कर दिया। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि जम्मू के पहाड़ी क्षेत्र आतंकियों के लिए आश्रयस्थल रहे हैं। इन जंगलों में छिपकर आतंकी हमलों को अंजाम देते थे। करीब दो दशक पूर्व भी यह क्षेत्र आतंक का गढ़ रहा था और कश्मीर से अधिक हमले इस क्षेत्र में होते थे। अब रियासी में निर्दोष महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया। फिर कठुआ में सेना के वाहन पर हमला चिंता की बात है। अब समय ठोस निर्णय लेने का है। राजौरी, पुंछ के बाद रियासी और कठुआ के हमले बताते हैं कि सेना को एक और निर्णायक प्रहार के लिए छूट देनी होगी। इस बार निर्णायक कार्रवाई हो और ऐसी हो कि पाकिस्तान कुछ भी करने से पहले सौ बार सोंचे।

नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की निगाहें भारत पर टिकीं

– मिथिलेश नौटियाल

नकदी संकट और आतंकवाद से जूझ रहे पाकिस्तान की निगाहें भारत पर हैं। भारत के साथ व्यापार संबंधों को बहाल करने पर गंभीरता से विचार हो रहा है।

एक तरफ आतंकवाद से लड़ाई और दूसरी तरफ गंभीर नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में पड़ोसी देश ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने की बात कही है। विदेश मंत्री इशाक डार के बयान से संकेत मिल रहा है कि पाकिस्तान अब भारत के प्रति राजनयिक रुख में बदलाव चाहता है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगस्त 2019 से व्यापार संबंध रुके हुए हैं। डार ने कहा कि इन संबंधों को बहाल करने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। डार ने ब्रूसेल्स में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बताई। उन्होंने भारत के साथ व्यापार गतिविधियों को शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कारोबारी भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करना चाहते हैं। डार के अनुसार पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार संबंध बहाल करने पर गंभीरता से विचार करेगा।

जिस तरह से इशाक डार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को बहाल करने पर टिप्पणी की, उससे साफ है कि पाकिस्तान भारत के प्रति राजनयिक रुख में बदलाव का संकेत दे रहा है। दरअसल भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू–कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों को कम कर दिया। उधर जम्मू–कश्मीर पर भारत पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है। भारत कह चुका है कि जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश देश के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से थे।

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी। शरीफ ने भी एक्स पर अपनी पोस्ट में पीएम मोदी को धन्यवाद कहा था। शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार आठ फरवरी के चुनावों के बाद सत्ता में आई। अपने कार्यकाल के शुरुआत में ही शहबाज शरीफ के सामने गिरती अर्थव्यवस्था एक बड़ी चुनौती है।

कृष्ण चरित मानस

गीता स्कंद

अष्टादश अध्याय

डां शशिकान्त तिवारी 'विनोद जी' महाराज
संस्थापक मुस्कॉन

सात्विककर्ता सिद्ध धैर्य उत्साह युक्त।
सगंरहित निर्विकार अहंकार मुक्त।।
राजसकर्ता कर्मफल चाहे रागी लोभी आसक्तियुक्त।
हिंसक अशुद्ध आचरण राजस होते हर्ष शोक में लिप्त।
दोहा।।
तामसकर्ता शिक्षाहीन घमंडीअयुक्त।
शठ शोकाकुल दीर्घसूत्री आलसीधूर्त।।
बुद्धिधृति भेद गुण तीन प्रकार।
धनंजय सुन संपूर्ण विभागी मेरे विचार।।
प्रवृत्तनिवृत्त कर्म अकर्म भयाभय जाने।
सात्विकबुद्धि पार्थ मोक्ष बंधन माने।।
धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य ना जाना।
हे पार्थ वह बुद्धि राजसी माना।।
पार्थ जो बुद्धि अधर्म को धर्म माने।
तामसी बुद्धि सब विपरीत ही जाने।।
ध्यानयोग से धारे इंद्रिय मन प्राण।
सात्विक धृति वह अव्यभिचारी पार्थ।।
फलांकाक्षी धर्म अर्थ और काम।
आसक्तियुक्त धृति है राजसी पार्थ।।
निद्रा भय उन्मत्तता शोक विषाद।
जो धारे तामस धृति है पार्थ।।
हे भरत श्रेष्ठ अब सुन मुझसे सुख के भी तीन विधान।
सात्विक सुख जिसमें साधक रमण करे सेवा भजन औ ध्यान।।
दोहा।।
आरंभ में लागे बिष समान।
परिणाम अंत में अमृत पान।।
परमात्मा विषयक बुद्धि प्रसादा।
उत्पन्न होहि सात्विक सुख अगाधा।।
सुख विषय इंद्रिय संयोगा।
माना सुख यह राजस होगा।।
भोग काल में अमृत परतिती।
विषतुल्य परिणाम राजस रीति।।
सुखभोग परिणाम आत्मा मोहे।
निद्रा आलस्य प्रमाद तामस होवे।।
प्रकृति उत्पन्न तीन गुणी ना होऊ।
पृथ्वी आकाश देवता ऐसा ना कोऊ।।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार।
परन्तप कर्मस्वभाव विभक्त गुण आधार।।
ब्राह्मण के है स्वाभाविक करमा।
वेदशास्त्र अध्ययन अध्यापन करना।।
ईश्वर वेद परलोक में श्रद्धा धरे ब्राह्मण शुद्धि क्षमा ज्ञान विज्ञान।
इन्द्रियदमन निग्रह करे धर्म हेतु कष्ट सहे सरल होय ब्राम्हान।।
दोहा।।
क्षत्रिय के हैं स्वाभाविक कर्म।
शौर्य तेज दक्ष दान युद्ध धैर्य।।
कृषि गौवर्धन वाणिज्य वैश्य कर्म।
सेवा परिचर्या है शूद्र के कर्म।।
अपने स्वकर्म नर परम सिद्धि पाते।
सुनो विधि कर्मकर सिद्धि कैसे पाते।।
जो परमेश्वर जगतव्याप्त भूत उत्पति।
कर्म से परमेश्वर पूजे पाते सिद्धि।।
स्वधर्म श्रेष्ठ है सकलगुण हीना।
परधर्म आचरण करो कबहू ना।।
स्वभाव नियत कर्म करो स्वधर्मा।
पाप ना मिलिहे अपना कर कर्मा।।
कौन्तेय ना त्यागो सहजकर्म दोषयुक्त।
धुआ अग्नि भांति सबकर्म दोषयुक्त।।
सर्वत्र आसक्ति स्पृहा रहित जितात्मा।
नैष्कर्म्य सिद्धि परम सन्यास पावे आत्मा।।

(क्रमशः)

Defeating the Diabolic Kashmir-Khalistan Plot

Lt Gen K J Singh

Pakistan has embarked on a questionable endeavour, packaged as 'Azme-Ishteqam' (Resolve for Stability). Coping with a rogue Pakistani Taliban, formally known as Tehreek-e-Taliban- e-Pakistan (TTP), is a dream turned-nightmare for the Pakistani army, which is other wise known to misuse tanze ems (used for terrorist organisations) as strategic assets. It is a desperate measure to retain relevance, placate a peeved China and deflect attention from domestic chaos. The last one is indeed ominous for us. In Inter-Services Intelligence (ISI), career progression is mainly a function of ability to foment trouble across the Line of Control. Consequently, the dreaded K-2 (Kashmir-Khalistan) cell seems to be in an overdrive. Multiple terrorist attacks south of Pir Panjal and an at tempt to extend the arc of terrorism to Kathua/Samba down to Gurdaspur are all apparent manifestations of this mischievous design. Pakista ni proxies are concurrently scouting to ramp up activity north of Pir Panjal.

Likely ISI Design

The possible aim is rade the current state of normalcy and disrupt Indian plan to hold J&K elections. This is accompanied by a he ightened narrative to high light electoral success of se paratist/radical candidates in Baramulla in Valley, along with Khadoor Sahib and Fa- ridkot in Punjab. The timing seeks to unsettle the new govt that has lost some traction due to reduced mandate and the Shri Amarnath Yatra.

China would only be too pleased and hope for reduced terrorist acts against CPEC. It would also wish for India to divert focus and resources from an unresolved stand off on the Line of Actual Control (LAC). It is relevant to reiterate that the vacuum created by pulling out of Rashtriya Rifles (RR) formations and Central Armed Police Forces (CAPFs) not being able to sta bilise the grid, have been exploited by terrorists.

Mitigating strategy: Punjab

The first caution is to notto T fall into the ISI trap of conflating two problems in separate regions and with unique dimensions, making it appear as a mega collapse. The problem in Punjab can be nipped in the bud even before it finds traction. It would also be pragmatic to prevent amp elections. to deg lification of separatist narra- tive as the success of candida tes in isolated pockets doesn't reflect widespread angst.

In Punjab, results can be attributed to anti-incumben cy, scepticism and even a 'Robin Hood' syndrome. Punja bis are known to take up cud gels for all and sundry, at the slightest provocation. Stereotyping all Punjabis as Khalistanis is most avoidable. There is a dominant perception that central agencies are engaged in fomenting trouble. While separatism has to be condemned, why should natio-nalist, sociocultural organisations celebrate the death anniversary of Shabheg Singh of Blue Star notoriety? In this, they could even misread success in

Faridkot, as complementary to this narrative. It would have been appropriate if all nationalist parties had demonstrated their genuine commitment and withdrawn their candidates to pose a combined challenge, especially when ground reports indicated a surge in favour of these two candidates.

While Punjab has a reputation for contrarian ethos, central and state govern ments need to forge a consensus on border management and combating Pakistani de signs. An immediate and tho rough audit of police deploy ment is recommended. Asar my commander, I had flagged the tendency of posting state service officers in border dis tricts. They were not only complicit, but also in league with local mafias. We cannot afford a repeat of SSP Salwinder, who not only ignored the mansion of drug-running taxi driver Ikagar but was al so roaming in border with a diamond trader. Bamyal, where Pathankot terrorists commandeered Salwinder with his associates, is again in news.

It is heartening that villa gers of Arnia (Samba) once again sensitised security forces about the presence of ter rorists. They are a critical link to the anti infiltration grid, which needs periodic review. As the nation upgra des its connectivity grid, it will be appropriate if salien ce and vulnerability of Pat hankot-Kathua-Samba-Jam- mu link, which is in show window, is reduced by buil ding redundancy through rail-road link, along Dhar-Ran- jit Sagar-Udhampur axis.

Conflict Resolution: J&K

My friends in the Valley, while agreeing that all leaders had feathered their nests, are stridently in demand for the return of 'jamu hariyat' (democracy). They accept that under central ru le, things have improved sig nificantly but yearning for self-governance is all perva sive. The desire to craft the king's party and place them at the helm through manipulation is likely to be counter productive in the long run. It will be a repeat of similar mistakes of fixed elections. Let us trust the 'awam' (peo- ple) and hold free and fair A bold and large hearted move to restore state hood may turn the tide of public opinion on both sides of the LoC.

It is fairly apparent that the security grid needs reori entation and reinforcements. It is learnt that additional forces to guard the yatra have be en inducted. It may be worth while to induct one/two Assam Rifles sectors, as they ha ve enviable track-record during their previous deploy- ment in J&K. It is learnt that CRPF is beingsanctionedasa specialised mountain batta lion. It is high time that they upgrade themselves and take up mandated primary tasks. More importantly, become accountable for the same.

The Way Ahead

It is appropriate to recount Isappropriate to reco told GOC 4 Corps, in response to his plan to eliminate alllea- ders of ultra groups. He re- portedly advised him to spare a few sensible ones for conflict resolution. Mainstreaming of rebels is an essential imperative. We can recount the transition of Laldenga from rebel to Mizoram CM and Subash Ghising in Gorkhaland.

In border states, competi tive centrifugal tendencies exist amongst parties, reflec ting local aspirations is natural. Regional parties, though high in rhetoric which panders to their vote bank, have utility as a buffer against ex- tremist parties. Instead of re-gional party-mukt (free) polity, we need responsible ones. Conflict resolution requires a patient and a well-thought- out action plan orchestrated by genuinely neutral domain experts, supported by re sponsive administration.

Space Force Dynamics: Shaping the future of military operations

Maj Gen (Dr) Ashok Kumar (Veteran)

30 June 2024. The world space may have multiple connotations but the space in all manifestations is moving more intensely for the military use. In that, it is the 'outer space' which is gaining special significance. This is normally the region beyond 100 km from Earth's surface for understanding the Earth's outer space where the present era of contest is building up with every passing day. It is also expanding its scope beyond the Earth's outer space with scientific revolution taking place at a fast space.

While the humans have probably known about these issues close to 1000 BCE, the modern discovery is just about a hundred-year-old when first meaningful observations were made though the presence of such a vacuum between Earth and Moon came to the fore sometime in 17th Century. At this juncture, it is not important to focus on the ancient historical background but the way the outer space -now termed as space is being used by the majority of the nations.

It all started at the closing moments of the Second World War when USA detonated two nuclear bombs in Hiroshima and Nagasaki in Japan. There is a strong theory gaining ground that USA probably did this to establish its supremacy in the post-World War 2 era as the war was coming to an end even without this action. USA was all set for the launch of final ground offensive from the island of Okinawa and backdoor negotiations had started between then USSR and Japan to give Japan an honourable exit. The rush thereafter followed to split Germany into West Germany and East Germany with former adopting democracy while latter adopted Communism. Both USA and USSR then poached German Engineers as they were best in the world at that time especially in the Rocket Technology. Since Rocket technology is the most crucial for transit or placing of anything and everything in the space, a close space race began between the two super powers.

With the advent of technology, the space started being utilized initially more focused on civil use purposes gravitating towards the dual use profile and now its weight has started shifting towards military use. In real sense, the basic thought of peaceful use of outer space already stands compromised.

The mankind has started exploring the outer space using multiple means like observation though powerful telescope and launch of

satellites with Soviets launching Sputnik1 on 04 Oct 1957. These kinds of efforts got repeated heating up space race between the two superpowers.

This was all changed when first human travel was made possible wherein Yuri Gagrin, a Soviet cosmonaut orbited the Earth on 12 Apr 1961. And of course, all the leads of Soviets were negated when USA succeeded in landing Neil Armstrong on moon in 1969.

To ensure some sanity amongst the nations, the Outer Space Treaty came into operation in Oct 1967. Its tenets highlighted that the space belonged to entire mankind, does not recognize the sovereignty of individual nations as prevalent on the Earth and prohibited placing of nuclear weapons/ weapons of mass destruction. Somehow, the provision of using it for the military use got left out which is being exploited even by the signatory countries. Space is emerging as one of the most contested frontiers wherein close to 100 countries are using the space actively by having satellites, conducting space research and alike. In fact, more than 70 countries have their own space agencies and the Nos will grow only. Not only this, there are more than 6500 operational satellites in addition to 3000 nonfunctional satellites and rocket bodies.

The initial focus of the countries was about knowing the celestial bodies, study Earth and use this for gaining knowledge & exploration but since all resources placed in the outer space needed a rocket to do that and rockets were primarily used for war fighting so slowly and steadily the outer space was readied / used for the military use. Some of the examples include:

Mapping of own country, adversaries and other countries of interest. Development of capability to get Geo-data even of the areas not mapped earlier in real time-frame.

Satellite imagery to notice the changes related to infrastructure Development and movement of forces and resources.

Provide satellite inputs on payment or otherwise to friendly countries. With participation of increasing private sector entities, the national barriers are also diminishing.

Movement of Long-Range Missiles, ICBMS and hyper sonic weapons against the adversary.

Development of Anti-satellite (ASAT) weapons to disrupt the satellites of the target countries.

Increased space habitation and countering those of adversaries.

Undermine effectiveness of space-based assets of adversaries.

Satellite guidance of out of sight missions be it for the UAVs/ Drones etc.

Use debris intentionally or unintentionally for neutralizing the efforts of the resources of the adversaries.

Realistically speaking, the era of space wars has already begun with countries positioning themselves favourably. Its full physical manifestation will unfold in times to come. It is important to look at Indian needs in this segment to look at whether Defence Space Agency is going to meet our requirements or will we need a Space Force on lines of USA. The Space industries will also need to focus on those areas where there is a definite need to look at Niche technologies which can meet our gaps/ concerns related to the Indian Defence Forces whether these be in the underwater domain or elsewhere. A closer partnership and re-energised eco system are the need of the hour.

FIGHTING THE DRAGON: INDIA'S BORDER INFRASTRUCTURE WAR WITH CHINA

Shivansh Singh
(Research Associate)

The longstanding border dispute between India and China is not merely a geopolitical conflict but a pivotal challenge with far-reaching implications for regional stability and security. India's response to China's assertive infrastructure development along the Line of Actual Control (LAC) has become central to its national security strategy. In recent years, India has significantly upgraded its border infrastructure to bolster territorial integrity and counterbalance Chinese ambitions. This includes improving road networks, constructing strategic tunnels, and enhancing air infrastructure. These developments aim not only to meet military needs but also to foster regional development.

Simultaneously, China has also expanded its infrastructure along the LAC, intensifying tensions and prompting military standoffs. The strategic importance of these developments is underscored by their role in shaping the ongoing territorial disputes and broader geopolitical dynamics in the region. As both nations continue to strengthen their positions, the LAC remains a focal point of competition, necessitating ongoing infrastructure enhancements to maintain security and deter conflict.

Road Infrastructure Expansion

India has embarked on an extensive road-building campaign near the LAC. These roads are pivotal for improving connectivity and logistics, allowing rapid mobilisation of troops and equipment. Key projects include the black-topped road on the north bank of Pangong Tso towards Finger 4 and the Sela Tunnel Road project, which will be the world's longest bi-lane tunnel above 13,000 feet.

The Border Roads Organisation (BRO) has seen a significant rise in its capital budget over recent years. In the fiscal year 2023-24, the budget increased to ?5,000 crore, marking a 43% rise from the ?3,500 crore allocated in 2022-23. For 2024-25, the budget saw a substantial increment, reaching ?6,500 crore.

The BRO has executed 90 infrastructure projects totaling Rs 2,941 crore across 11 states and Union Territories to address the border infrastructure gap with China. These include 36 projects in Arunachal Pradesh, 26 in Ladakh, and 11 in Jammu and Kashmir. This follows 103 projects completed in 2022 (Rs 2,900 crore) and 102 in 2021 (over Rs 2,200 crore).

In the past three years, the BRO has completed 330 projects costing ?8,737 crore, significantly enhancing the strategic mobility of the Indian armed forces along the LAC.

The development of these roads is crucial for strategic access and operational readiness. For instance, the 130 km Sasoma-Saser La-Brangsa-Gapshan-Daulat Beg Oldi (DBO) Road in Eastern Ladakh provides an alternative route to India's northernmost military base.

Additionally, the 62,214 km of roads, 1,005 bridges, seven tunnels and 21 airfields constructed by the BRO since its inception highlight India's commitment to infrastructure enhancement along its borders. Despite the progress, challenges such as difficult terrain, weather conditions, and remote locations continue to impede construction efforts. The BRO is set to begin construction on the 4.10-km-long Shinkun La Tunnel, which, upon completion, will be the world's highest tunnel at an elevation of 15,800 ft, surpassing the 15,590 ft Mila Tunnel in China. India is also progressing on a 298-km all-weather road from Manali to Western Ladakh and Zanskar, with 65 percent of the construction complete and expected to open by 2026.

Air Infrastructure Developments

In contemporary military strategy, the development of air power-related infrastructure is essential for ensuring defence capabilities and maintaining deterrence in strategically significant regions. India's air infrastructure upgrades near the LAC have been substantial, particularly after key incidents like Doklam and Galwan. These upgrades leverage India's advantageous topography to maintain a strategic edge in the air domain. The construction of a second runway at the Leh airbase and upgrades to forward airbases like Daulat Beg Oldi and Fukche are notable developments. India is expected to complete a 2.7-km runway at the Nyoma airbase in Ladakh by October 2024. This project, noted as one of the most critical near the disputed border with China, will significantly enhance India's border infrastructure capabilities, according to BRO chief Lieutenant General Raghu Srinivasan.

These enhancements allow for better support of air operations and rapid deployment capabilities. India has also focused on extending its airfields to accommodate advanced fighter jets, UAVs, and reconnaissance aircraft. However, China's parallel development of airfields and deployment of additional fighters and drones presents a competitive challenge. China's airfields, such as Kashgar, Hotan, Ngari Gunsa, and others, enhance the PLA's (People's Liberation Army) ability to project air power along the LAC.

Rail Connectivity and Tunnels

Rail infrastructure complements road and air networks, offering efficiency that is vital to military logistics. But rail connectivity remains a relatively underdeveloped aspect of India's infrastructure along the LAC compared to China. However, plans are underway to improve rail links to bolster logistical capabilities. In addition to rail improvements, India has focused on constructing strategic tunnels to enhance all-weather connectivity and reduce transit times.

Key tunnel projects include the Sela Tunnel in Arunachal Pradesh and the Shinkun La tunnel in Ladakh. The Shinkun La tunnel holds significant strategic importance for the military due to security considerations vis-à-vis threats from China and Pakistan. Its enhanced security profile surpasses that of the Srinagar-Drass-Kaksar-Kargil highway near the Line of Control (LOC) and the Manali Upshi-Leh highway near the Line of Actual Control (LAC). The Sela Tunnel, in particular, provides all-weather access to the Tawang region, crucial for military logistics and rapid troop deployment. These tunnels mitigate the effects of harsh weather and improve the mobility of troops and equipment.

Vibrant Villages Programme

India's Vibrant Villages Programme aims to comprehensively develop border villages to improve the quality of life for residents and enhance regional stability. This initiative involves constructing roads, bridges, and essential infrastructure in remote border areas, fostering economic development, and strengthening local communities.

The programme's focus on providing

amenities and infrastructure in these villages also has strategic implications. By improving living conditions and connectivity, India can reinforce its presence in border regions, reducing the incentive for out-migration and strengthening national security.

China's Infrastructure Build-Up

Despite India's advancements, China continues to expand its infrastructure along the LAC. Over the past four years, China has constructed roads, bridges, and tunnels to enhance last-mile connectivity to its forward positions. The completion of a road from Samzungling to the Galwan Valley exemplifies China's efforts to shorten troop mobilization routes.

China's infrastructure development includes constructing new bunkers, camps, underground shelters, artillery positions, radar sites, and ammunition dumps. The PLA has also improved its air combat capabilities by deploying additional fighters, drones and air defence systems. China's dual use 'Xiaokang' border villages further reinforce its positions and territorial claims.

Military and Logistical Support

India has also taken steps to improve living conditions and logistical support for its troops deployed along the LAC. Upgraded living facilities, including modern habitats with water, electricity, and heating, have been established in regions like Eastern Ladakh. The introduction of solar-heated, insulated Ladakhi shelters and the procurement of high-altitude winter clothing highlight India's commitment to troop welfare.

Additionally, India has commissioned specialized insulated bunkers capable of withstanding extreme temperatures, ensuring that troops remain operational even in harsh winter conditions. These bunkers are constructed to house at least 120 troops. These measures are crucial for maintaining a robust military presence in the region and ensuring that troops are well-prepared for extended deployments.

Comparative Analysis: India vs. China

In comparing the infrastructure developments of India and China along the LAC, several key points emerge. China maintains a lead in terms of the scale and rapidity of its infrastructure build-up. China's extensive road networks, airfields, and dual-use villages allow for swift mobilisation and logistical support for its forces.

However, India's strategic tunnel projects, airfield upgrades, and road networks provide significant enhancements to its border infrastructure. India's efforts to match China's capabilities are evident in its rapid infrastructure development and military deployments. While China retains a numerical advantage in terms of infrastructure, India's focus on quality and strategic positioning provides a counterbalance.

Conclusion

India's infrastructure development along the LAC reflects a strategic shift towards enhancing military capabilities and regional development. The expansion of road networks, air infrastructure, and strategic tunnels underscores India's commitment to improving connectivity and logistical support in border areas. Despite facing challenges such as difficult terrain and harsh weather, India has made significant strides in infrastructure development, providing a counterbalance to China's extensive build-up along the LAC.

China's relentless infrastructure expansion poses ongoing challenges for India, necessitating continuous efforts to match and counter China's capabilities. However, India's comprehensive approach, including the Vibrant Villages Programme and the focus on improving living conditions for troops, highlights a balanced strategy that addresses both security and developmental needs. As India continues to strengthen its border infrastructure, the strategic dynamics along the LAC will remain a critical aspect of its defence and regional development policies

Why Should Be India Considering The F-35 Fighter Jets

Cdr Sandeep Dhawan (Retd)

Hours before the US Defence Secretary Robert M. Gates's visit to Beijing in January 2011 aimed at improving defence ties, China's military conducted a test flight of a new stealth fighter jet. Surprisingly, Gates wasn't aware of the usual Chinese military's show of strength gimmick during any important meeting. He enquired with President Hu Jintao, if this was due to his visit. But Hu Jintao kept a poker face, feigning any awareness.

The semi-stealth fighter in question was J-20. It's the same fighter that has a geometrical resemblance to the long-defunct Russian MiG 1.44 program. But J-20's closer inspection reveals the incorporation of Lockheed Martin's F-22 and F-35 features. All thanks to Chinese businessman Su Bin, who stole thousands of Lockheed Martin files and supplied them to the Chinese military. He got away with just 46 months of jail term, making the Chinese military take a giant technological leap.

However, neither Su Bin's hacking techniques nor Lockheed Martin's lack of safeguarding its data is any of India's concerns. India in general and the Indian Air Force (IAF) in particular are concerned because the same fighters are now getting deployed at Shigatse's dual-use airport in Tibet, just 150 km from the Indian state of Sikkim. China is also making a pitch for the Pakistani Air Force to acquire an unproven F-35 clone, the J-31 fighter jet.

People's Liberation Army Air Force (PLAAF) currently has over 200 J-20s in service. But with a 100-per-year production capacity, they would add another 800 J-20s to their fleet in the next eight years. That means by 2032 the number of J-20 squadrons would alone be over 45 with a fleet size of 1000. A number greater than all the fighters in the IAF's inventory.

The Number Game

With the planned ?5,300 crore, 50 years life upgrade, the IAF will be able to extend the life of 61 MiG-29UPG until 2035. One must remember that the MiG-29's first life extension from 25 to 40 years was undertaken in the mid-2000s. On the other hand, with the 13-year-long ongoing upgrade and the purchase of 12 used Mirage-2000s from Qatar, the IAF may achieve 47 serviceable Mirage-2000s lasting till the late 2030s. However, the serviceability rate of these vintage aircraft has always been a concern.

The IAF also has six SEPECAT Jaguar squadrons. Out of 140 aircraft acquired

starting from 1979, only 117 are left in the inventory and struggling to maintain the serviceability rate. To tide over the situation India bought 31 decommissioned airframes, engines, and spare parts in 2018. In the same year, HAL started an upgrade of various weapon, navigation, and avionics suites. Currently, the IAF is seeking nine more used Jaguars from the Royal Air Force (RAF). The whole game plan is to extend the life of 117 Jaguars beyond 2035.

Presently, there are 15 Su-30MKI (as reported by Janes), 6 Jaguars, 2 MiG-21 Bison, 3 Mirage-2000, 3 MiG-29UPG, 2 Rafale, and 2 Light Combat Aircraft Tejas Mk1 squadrons in the IAF. This takes the number of fighter squadrons in the IAF to 33. But one must keep in mind that Su-30MKI squadron numbers have been bolstered from 12 to 15 using the same pool of 263 fighters.

The squadron number had bottomed out at 29 in 2020. In 2025 the remaining two MiG-21 Bison squadrons with 40 odd aircraft will be numberplated, taking the squadron strength back to 31. The additional 21 MiG-29UPG and 12 Su-30MKI orders the government of India announced in 2020 would have arrested that slide. However, the government eventually cleared only 12 Su-30MKI in September 2023.

The Timeline

The Tejas program has given the IAF some breathing space. The IAF had ordered 40 indigenous Tejas Mk-1 fighter jets and taken deliveries of 34. The IAF also ordered 83 advanced Tejas Mk-1A. An additional order of 97 Tejas Mk-1A is pending with the Cabinet Committee on Security (CCS) for approval. The deliveries of Mk-1A are likely to commence by July 2024.

At the production rate of 24 aircraft per year, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) is likely to complete the deliveries of 83 fighters by the end of 2028. The additional 97 fighters, if approved before 2028, would take another four years for the deliveries, i.e. 2032. The impressive 180 Tejas Mk-1A numbers would form an additional 10 fighter squadrons, reducing the squadron shortfall drastically. All these calculations would work out provided the HAL keeps up its promise of 24 deliveries per year.

Tejas Mk-2 was scheduled to make a rollout in 2023, however, it has been pushed forward to 2026. There are several reasons for the delay, however mainly it is due to an increase in the indigenous components from 65% to 80%. The first flight is expected to take to the skies by 2028 and production to start by 2030. At present the order book stands at 108 Mk-2s, however, the government of India has indicated that the numbers may be bumped up to 200.

India's ?15,000 crore 5+ Gen Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) stealth fighter jet program was cleared by CCS in March 2024. The first flight is likely to be by early 2029 and production by 2034-35. The IAF is likely to acquire a total of seven AMCA squadrons — two AMCA Mk1 and five AMCA Mk2.

The Acquisition Plan

Keeping in mind the depleted strength of the fighter squadrons, the IAF floated a Request for Information (RFI) in 2004 for the purchase of 126, 4.5 Gen, Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA). The whole proposal remained on paper for a decade. Finally, the RFI was scrapped in April 2015 when the government informed that they intended to buy 36 Rafale fighter jets from France in fly-away condition. In 2018 the MMRCA appeared in a new avatar of Multi Role Fighter Aircraft (MRFA). This time the fighter numbers were pitched at 114. Eight Original Equipment Manufacturers (OEM) are

in the fray.

The government of India has learned from the mistakes of acquiring Mirage-2000 and Rafale fighter jets in fly-away condition. In the latest move, the Indian government has made a policy switch. Now the 114 MRFA deal would be only with a vendor who is ready to set up the manufacturing facility for the entire aircraft in India. The manufacturing would be in a joint venture with a local partner along with a complete technology transfer. An announcement in this regard should be made soon.

India's Gen 5+ Stealth Dream

From the foregoing, it is amply clear that India's 5th Gen aircraft and stealth fighter dream would not fructify for over a decade, even if all the timelines were met.

Off late a marketing blitz has come to light. Several articles have appeared in the Western media about how and why India should buy Lockheed Martin's F-21 or McDonnell Douglas's F-15EX. There are a few articles also appealing to the US administration to sell F-35 stealth fighters to India. The US has barred the countries possessing the Russian S-400 missile defence system from procuring F-35. This includes India and Turkey.

While the F-21 is based on the mid-1970s design of the F-16, the first F-15 was built in 1972. Both aircraft are very capable, however, these requirements could be met by the ongoing Tejas Mk-2 program and Su-30MKI. Therefore, India should not consider any US fighter other than the F-35 Joint Strike Fighter.

A recent statement by the Indian Defence Minister Rajnath Singh is noteworthy. While commenting on China's third aircraft carrier he stated that India would soon commence building its third aircraft carrier and plans are afoot to make five or six aircraft carriers. This is a very interesting statement. Was he hinting at Japan's Kaga helicopter carrier type of ships along with F-35B Lightning II short take-off and vertical landing (STOVL) fighters? Japan has recently converted a helicopter carrier Kaga into an aircraft carrier. Kaga's sister ship Izumo would also be ready in the new role by 2027.

Interestingly, Japan has 42 F-35Bs on order for this purpose. Since India has decided to have a local manufacturing of MRFA. If the US allows India to manufacture F-35s domestically, it would be a big boost to the F-35 program. It could also bring the cost of the F-35 production and operations down.

The IAF cannot wait for a decade to have 5th-Gen stealth fighters in its inventory when the enemy is lurking at the border. By the time the IAF gets Tejas Mk-2 or AMCA, China would have stolen 6th-Gen fighter designs like — NGAD, Tempest, or FCAS, reverse-engineered and mass-produced them.

The Win-Win Proposition

An F-35 production line in India could be a far-fetched but worthwhile idea. The United Arab Emirates (UAE) cancelled order of fifty F-35 order in 2021. India could look at acquiring similar numbers as part of MRFA. This would enhance the IAF capabilities while safeguarding India from the usual American threat of sanctions.

The F-35 production is severely affected due to the pending Technology Refresh 3 (TR-3) upgrade. India's trained and huge talent pool would come in very handy in resolving present and future issues. The local production would also facilitate the localization of spares and components, F135 engine labor issues, as well as provide services to other regional operators. Last but not least even a partial technology transfer would be a great learning experience for India's future fighter jet programs. This proposition is a win-win for both India and the USA and is worthy of serious thought.

Inauguration of Captain Manoj Kumar Pandey PVC (P) Stadium Marks 25 Years of Kargil Victory

In a tribute to the heroes of Operation Vijay, a new multipurpose stadium was inaugurated at Garkhone in the Kargil district of Ladakh. The stadium is named after Captain Manoj Kumar Pandey, PVC (Posthumous), who was awarded the Param Vir Chakra for his bravery during the Kargil War.

The General Officer Commanding of the Fire and Fury Corps presided over the ceremony, dedicating the stadium to the community members of Aryan Valley and the bravehearts of Operation Vijay.

This development is part of the 25th anniversary celebrations of Kargil Vijay, also known as #KVDRajatJayanti, honoring the sacrifices and valor of the soldiers who fought in the 1999 conflict.

The Captain Manoj Kumar Pandey PVC (P) Stadium aims to provide a space for sports and community events, fostering unity and a spirit of resilience among the residents.

The establishment of the stadium not only commemorates the historical significance of Kargil Vijay but also serves as a lasting monument to the courage and dedication of the Indian Armed Forces.

It stands as a reminder of the heroism that continues to inspire future generations in Ladakh and across the nation.

F-No- 17/4/2021-P&PW(Coord.)-7648
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi,
24th June, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 100 Days Action Plan of DOPPW- Special Campaign for timely and qualitative redressal of Family Pensioners' Grievances during the period July 1-31, 2024-reg.

Department of Pension and Pensioners' Welfare (DoPPW) is mandated to ensure welfare of pensioners, especially Family Pensioners, out of which a major segment is constituted by women pensioners. Presently, Family Pension grievance cases account for about 20-25% of the total receipt of grievances on CPENGRAMS Portal.

2. As a part of the Government's 100 days Action Plan, DOPPW will launch a Special Campaign for timely redressal of Family Pension cases, pending on the CPENGRAMS portal from 01st July, 2024 to 31st July, 2024 in mission mode approach. This initiative will be conducted across all Central Ministries/ Departments and their attached/subordinate offices. The guidelines for the successful execution of the campaign are outlined as under:

i. DoPPW will share the list of pending Family Pension grievance cases, as on 15.06.2024, on CPENGRAMS Portal with the Ministries/Departments for redressal in the campaign.

ii. The Ministries/Departments shall nominate Nodal PG officers well versed with the Pension rules/procedures for qualitative and expeditious redressal of Family Pension grievances.

iii. DOPPW will oversee the implementation of the campaign and provide necessary assistance on rule position and procedure as deemed for support to Ministries/Departments. For further information, Ministries/Departments may contact Dr. Pramod Kumar, Director, DOPPW, Telephone no.-011-24654734, E-mail: pramod.kumar79@gov.in.

iv. The prime objective of the campaign is to provide qualitative redressal of the Family Pensioners' grievances. Hence, grievances should be closed on CPGRAMS Portal, only after conclusive redressal.

v. The Action Taken Report (ATR) may be updated on the CPGRAMS Portal latest by 05.08.2024. The relevant order/document including PPO/letter/e-mail is also to be uploaded along with the ATR.

vi. Success stories/Best practices may be widely disseminated by the concerned Ministry/Department through PIB/tweet and copy endorsed to this Department. The hashtag of the campaign is #SpecialCampaignFamilyPension.

4. All the Ministries/Departments are requested to adopt the above guidelines for successful implementation of the campaign.

(V.Srinivas)

Secretary to the Government of India

To,

Secretaries of the Ministries/ Departments

Chairperson/DG of the Organizations.

(As per list enclosed)

गतिविधियां (Social Activities)

– जे. बी. एस. चौहान

जयपुर (राजस्थान)

अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जयपुर प्रांत ने आज नीम का थाना व खेतड़ी में प्रवास किया । नीमकाथाना इकाई कई वर्षों से निष्क्रिय थी तथा इसके सक्रिय बनाने एवं सदस्य संख्या बढ़ाने की आवश्यकता थी। टीम ने पहले नीमकाथाना संयोजक हवलदार वीरेंद्र सिंह के आवास पर बैठक की जिसमें 7 नए सदस्य जोड़े गए उसके पश्चात खेतड़ी में विवेकानंद पब्लिक स्कूल में दूसरी बैठक की जहां 9 नए सदस्य जोड़े गए। इन बैठकों में एअर कमोडोर चंद्रमोली ने काफी उत्साहवर्धक उद्‌बोधन दिया जिससे नए सदस्यों में जोश का संचार हुआ एवं इकाई पूरी तरह सक्रिय हुई। प्रदेश महासचिव कमांडर बनवारी लाल ने नए सदस्यों को संगठन के उद्देश्य तथा सदस्यता की जानकारी दी। टीम के अन्य सदस्य श्री डालसिंह शेखावत, जयपुर प्रांत सचिव, भवानी सिंह चारण, प्रांत संगठन सचिव, HFO सुरेंद्र पारीक प्रदेश कोषाध्यक्ष हवलदार नव किशन भूरिया, सीकर इकाई अध्यक्ष ने सराहनीय सहयोग किया।

वडोदरा (गुजरात)

वीर बहादुर योद्धा फील्ड मार्शल सैम मानेकशा जी को उनकी पुण्यतिथि पर सौ–सौ सलाम, उनकी पुण्यतिथि पर गुजरात वडोदरा मे राष्ट्रीय मंत्री सार्जेंट अशोककुमार चावड़ा, प्रदेश अध्यक्ष ले.कर्नल अमृतलाल मकवाणा, प्रदेश वरिष्ट उपाध्यक्ष सार्जेंट दिनेशभाई पटेल, प्रदेश उप महामंत्री सार्जेंट संगीतकुमार झा , वडोदरा के महामंत्री सार्जेंट केतनभाई त्रिवेदी, वडोदरा कोषाध्यक्ष जे डब्लू ओ पराग शाह और सदस्य हवालदार जयसुख पनसुरीया द्वारा माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी गयी।

सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के तत्कालीन अध्यक्ष थे जिनके अद्‌भुत नेतृत्व में भारत ने सन् 1971 में हुए भारत–पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त किया था जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ था। राष्ट्र के प्रति निष्ठा अदम्य साहस और उत्तम युद्धकौशल के लिए मशहूर, भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्णिम दस्तखत करने वाले सबसे ज्यादा चर्चित और कुशल सैनिक कमांडर पद्‌म भूषण, पद्‌म विभूषण सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। अपने 40 साल के सैनिक जीवन में उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के अलावा चीन और पाकिस्तान के साथ हुए तीनों युद्धों में भी भाग लिया था। उनके दोस्त उन्हें प्यार से सैम बहादुर कहकर बुलाते थे।

झांसी (उ.प्र.)

दिनांक 18 जून 2024 सुबह 8 बजे, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद झांसी के तत्त्वाधान में संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा अमर शहीद वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के पावन अवसर पर महारानी लक्ष्मीबाई पार्क में स्थित विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और दो मिनिट का मौन रखकर वंदन किया गया।

इस पावन अवसर पर संगठन के अध्यक्ष फ्लाइंग ऑफिसर एसएस प्रसाद, महासचिव देवेश खरे, कोषाध्यक्ष सूबेदार केएम पाण्डेय, उपाध्यक्ष कैप्टन एसपी त्रिपाठी, कैप्टन राजवीर, फ्लाइंग ऑफिसर एमएच निगम, सूबेदार केके मिश्रा, नायब सूबेदार पुष्पेंद्र, जूनियर वारंट ऑफिसर केएन मालवीय, जूनियर वारंट ऑफिसर अतुल त्रिपाठी, सूबेदार मेजर जेएन शर्मा, नायब सूबेदार आरकेएस भदौरिया, हवलदार आरके विश्नोई, सार्जेंट श्याम

प्रकाश, मनोज राजावत, स्वामी प्रसाद, परशुराम, अब्बास अली, ठाकुर प्रसाद, आरबीएस तोमर,मान सिंह यादव, सूबेदार राज कुमार सिंह, हरी राम, शंभू दयाल, आरके श्रीवास्तव, ओमप्रकाश लोधी, ओमप्रकाश, पीएल अहिरवार, राकेश राजपूत, हवलदार केके तिवारी, हरिकिशन सिंह, इत्यादि बहुत से पूर्व सैनिक उपस्थित थे । सभी पूर्व सैनिकों को अल्पाहार के बाद मीटिंग का समापन हुआ। महासचिव देवेश खरे ने इस मौके पर आए हुए सभी पूर्व सैनिकों को धन्यवाद ज्ञापन दिया ।

महराजगंज (उ.प्र.)

अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गोरक्ष प्रान्त जिला महराजगँज में अधिक सँख्या में गोरखा पूर्व सैनिक रहते हैं। ईसीएचएस की सुविधा के अभाव में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमारी सँस्था ने पुरी ए जी एम में अपने अध्यक्ष जनरल विष्णु कान्त चतुर्वेदी के माध्यम से ईसीएचएस डायरेक्टर से आग्रह किया गया था।

27 जून 2024 को के एम सी हास्पिटल महराजगँज और रीजनल डायरेक्टर एलाहाबाद के दसखत के बाद इनपैनलमेण्ट किया गया। गोरखा सैनिकों के लिए यह सुविधा एक नई उर्जा के लिए रूप में जानी जा रही है।

लखनऊ (उ.प्र.)

14 जुलाई को अवध प्रान्त और लखनऊ महानगर के अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के लखनऊ में उपस्थित पदाधिकारियों की बैठक ब्रंदाबन योजना, लखनऊ में मेजर बीएस तोमर, अध्यक्ष अवध प्रान्त के कार्यालय में संपन्न हुई। संगठन के विषयों के साथ साथ तमाम सामाजिक विषयों और समस्याओं पर खुले मन से चर्चा हुई।

बैठक में निम्न पदाधिकारी उपस्थित हुए :– कर्नल आर वी सिंह – संरक्षक, मेजर बी एस तोमर – अध्यक्ष, अवध प्रान्त, कैप्टन सरोज सिंह – उपाध्यक्ष, अवध प्रान्त, सूबे. मे. जेबीएस चौहान – महासचिव अवध, सीपीओ डीडी पांडे, कोषाध्यक्ष, अवध, एडवोकेट पारिजात मिश्रा – अध्यक्ष लखनऊ, वारंट आफिसर एल एम पंत – उपाध्यक्ष लखनऊ, कैप्टन अरविंद सिंह – सचिव लखनऊ, कैप्टन बीएस कान्याल – प्रचार प्रमुख, लखनऊ, सूबे. मे. पी सुरेश कुमार।

आगामी 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाने हेतु तैयारी शुरू करने के लिए उचित प्रयास किये जायें ऐसा निवेदन एवं अपेक्षा की गई। लखनऊ सहित अवध प्रान्त के सभी जिलों के अध्यक्षों सचिवों से अपेक्षा है की गयी कारगिल विजय दिवस हर जनपद में मनाने का पूर्ण प्रयास हो। और आयोजन के उपरांत विवरण सहित कुछ फोटोज भी ग्रुप में शेयर किये जायें तो उत्तम रहेगा।

गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी (उ.प्र.)

अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, गोला की मासिक बैठक में संगठन को सुदृढ़ और गतिशील बनाने एवं सावन मेला में पुलिस का सहयोग करने का निर्णय लिया गया। ब्लाक सभागार में कृष्ण गोपाल त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। जिलाध्यक्ष दिनेशचंद्र शर्मा ने भूतपूर्व सैनिकों से संगठन को मजबूत बनाने के लिए और अधिक सदस्य बनाने पर बल दिया। राजेश्वर सिंह ने कहा कि परिषद के पदाधिकारियों ने पिछले सालों में भी सावन और चैत के महीनों में पुलिस का सहयोग किया है। इस बार भी पुलिस का सहयोग किया जाएगा। मासिक बैठक में विनोद कुमार तिवारी, प्रेमकुमार, देवप्रकाश, अकरम खान, अजय, भानु अवस्थी, हरपाल सिंह, प्रेमचंद वर्मा, जगदेश सिंह, नारायणलाल, वीरभद्र सेन, प्रमोद सिंह, वीरेन्द्र कुमार मिश्रा, गजेन्द्र प्रसाद, कुतुबुद्दीन, रामहरीश मिश्रा, चंद्रभाल, राकेश कुमार, महेशचंद्र वर्मा, महफूज अली, रघुनंदन प्रसाद, आशीष विश्वास आदि मौजूद रहे।